I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ORDINANCE, 1991

II. THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1991.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प उपस्थित करता हूं।

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 अप्रैल, 1991 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

यदि इजाजत हो तो मैं लंच के बाद बोलूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the House stands adjourned for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock.

[The Vice-Chairman (Shrimati Jayanthi Natarajan) in the Cnair]

THE BUDGET (RAILWAYS), 1991-92

THE MINSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI M. MALLIKARJUN): Madam, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 1991-92, in respect of Railways.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMEND. MENT) ORDINANCE, 1991

II. THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1991—Contd.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, हम इस समय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने पिछले दिनों भारत के इतिहास में एक ऐसा चुनाव देखा जो शायद सदियों तक भारत का जनमानस भुला नहीं पाएगा। किस तरह से इस चुनाव में अपराधी तत्व, देशद्रोही तत्व और विदेशी तत्व सक्रिय रहे और विश्व की एक मानीजानी जनतांत्रिक मशीनरी को खराब करने की कोशिश की गई, वह किसी से छिपा हुआ .हीं है। जब हम इस विधेयक पर बात करने के लिए सोचते हैं...

तो उस वक्त याद आती है अपने पूर्व पुरुषों की बातें कि आखिर पूर्वजों ने किस गणतांत्रिक अधिकार देने की बात सोची थी और किस गणतांत्रिक भारत को बनाने की बात सोची थी। इस गणतांत्रिक भारत को एक बहुत ही सुलझा हुआ संविधान उन्होंने दिया था और उस संविधान के माध्यम से हम सब को, इस मुल्क के 85 करोड़ जनता को कुछ अधिकार दिये थे। पर जब उन अधिकारों का दुरुपयोग होने लगा, जब उन अधिकारों को अपनी खुशी के लिये या अपनी सत्ता को बचाये रखने के लिए उसका प्रयोग होने लगा तो इससे इस मुल्क की जनता रोती है और इस मुल्क का दुर्भाग्य भरा इतिहास इस मुल्क की जनता लिखती है। जब आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को पढ़ेंगी तो वह इस कलंकित इतिहास को पढ़कर याद करेंगी कि किस तरह से इस मुल्क की आजादी के लिये उस समय के लोगों ने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमा। कहां है भगत सिंह कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुये कातिल में है, कहां वह भगतसिंह कि मेरा रंग दे बसंती चोला कहां वह विनय बादल दिनेश और कहां वह खुदीराम बोस जो यह कहते कहते फांसी के फंदे पर चढ़ गया कि :

"एक बार बिदाय दे मां
घुरे आसी
हांसी हासी पोरबो फांसी
देखबे जगत बासी
एक बार बिदाय दे मां"

उस इतिहास को याद करें। जिन्होंने हमें संविधान दिया उन पूर्वजों को याद करें जिन्होंने हमें एक सशक्त और बलिष्ठ ताकत के साथ संविधान दिया और जिसका दुरुपयोग हम रोज करते रहते हैं। महोदया, इब्राहीम लिंकन की वह मशहूर बात हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाते वक्त मद्देनजर रखी थी कि :

Democracy of the people, by the people and for the people.

मद्देनजर रखकर महोदया, हमने अपने संविधान के प्रियबल में लिखा कि :

We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign. Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them alls-

महोदया, कभी कभी इन सारी चीजों को हम भूल जाते हैं। कभी कभी अध्यादेश जारी करते वक्त इन चीजों का ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या अध्यादेश जारी करने जा रहे हैं और इस अध्यादेश से आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले गणतांत्रिक अधिकारों का क्या कहीं इससे हनन तो नहीं हो रहा है? शायद सब सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इस पर पूरी तरह से सोचने की जरूरत है कि ऐसे अध्यादेश क्यों जारी होते हैं। जब संविधान बन रहा था, उसके पहले इस मुल्क में जो भी डेमोक्रेटिक प्रथा थी, गणतांत्रिक अधिकार थे वे गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट 1935 के अनुसार चला करते थे। उसके बाद एक फंडामेंटल राइटस की सब कमेटी बनी जिसने कांस्टि-ट्यूएंट असेंबली के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस थी कि :

Universal adult suffrage must be granted by Constitution, Elections should be free, secret and periodic and elections should be managed by an independent Commission set up under Union law.

महोदया, डा० बाबा साहब अम्बेदकर जो संविधान सभा में कांस्टीट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनके मन की मंशा थी, उनके मन की इच्छा थी कि भारत के नागरिकों को इलेक्शन का अधिकार जो है वह फण्डामेंटल राइट्स में आना चाहिये। डा० राजगोपालचारी ने इसके विपरीत अपने दिमाग में कुछ रखा और कहा कि फण्डामटल राइट्स में रखने से शायद दिक्कत आ सकती है इसलिए यह फण्डामेंटल राइटस में इन्क्लूड नहीं हुआ तथा पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत के कहने पर इसके लिए एक सेपरट चेप्टर बनाया गया। महोदया, यदि उस दिन डा० बाबा साहब अम्बेडकर की बात यदि मान ली गई होती तो शायद आज यह बहस हमारे सदन में न होती। आज जम्मू-कश्मीर कि लोगों के अधिकारों का हनन न होता और जम्मू-काश्मीर के लोगों को पिछले चुनावों में वंचित रखा गया शायद यह न होता। इलेक्शन कमीशन की भी उस वक्त लोगों के दिमाग में बात आई थी कि हर एक स्टेट का अलग अलग इलेक्शन कमीशन हो और वही चलाएं। उस वक्त कांस्टीटयूयेंट असेम्बली के सदस्य कुलाधार चलिया जी ने कहा था—

If you cannot trust the honesty of your own. individuals, you can never make a success of democracy."

चलिया साहब की बात हमें बार बार याद दिला रही है कि आखिर किस ट्रस्ट की बात उन्होंने उठाई थी। यदि उस वक्त उनकी बातें मान ली गई होती तो आज यह बुरा दिन हमें न देखना पड़ता। गणतान्त्रिक अधिकारों का आज जो हनन हो रहा है वह न होता। महोदया, मैं इसलिए इन चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जम्मू काश्मीर में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय में वहां पर प्रेजीडेंट रूल लगाया गया और उस वक्त कहा गया—"राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाला प्रस्ताव

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

लोक सभा में 21–8–90 और राज्य सभा में 3–9–90 को पारित हुआ था अत: 18-7-90 को जारी की गई उद्घोषणा 2–3–91 के बाद लागू नहीं रहेगी"। इसके बाद फिर 6 महीने के लिए टाइम लेने के लिए उस वक्त के गृह मंत्री श्री सुबोध कान्त सहाय जी आए। उन्होंने कहा "भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की हाल ही की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस समय सुरक्षा और राजनैतिक हालात ऐसे हैं कि राज्य की सरकार को मौजूदा उद्घोषणा समाप्त होने के बाद संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना सम्भव नहीं होगा। राज्यपाल ने आगे कहा कि सुरक्षा बलों ने विघटनकारी तत्वों और उग्रवादियों की हरकतों को रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया हुआ है। कश्मीर के लोगों के स्वभाव में बदलाव भी दिखलाई दे रहा है। राज्यपाल ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि इन सकारात्मक हालात के बावजूद भी वहां सुरक्षा की स्थिति लगातार निराशाजनक और चुनौती-पूर्ण बनी हुई है। घाटी में और सीमा रेखा के पार पाकिस्तान में प्रशिक्षित उग्रवादी मौजूद हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में शस्त्र, गोली बारूद और विस्फोटक सामग्री उपलब्ध है। उन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों से तथा जम्मू-कश्मीर के उग्रवादी संगठनों से निरन्तर सहायता मिल रही है। राज्यपाल ने तदनुसार सिफारिश की है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को उसके समाप्त होने की तारीख: 6 महीने की और अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाए" यह मुद्दा। जम्मू कश्मीर की सरकार तोड़ कर वहां पर राज्यपाल का शासन लगाना और राज्यपाल शासन को आगे बढ़ाना और फिर चुनाव नहीं कराना। आप सब सोच रहे होंगे सही था मुद्दा फिर क्यों चुनाव नहीं कराए गए। पर महोदया, शर्म तो उस वक्त आती है जब हम इसके साथ साथ कुछ और राज्यों का इतिहास भी पढ़ लेते हैं। पर हम सब के सब बेशर्म हो चुके हैं। हम इतिहास को भूल जाते हैं.... (व्यवधान) महोदया, उसी के साथ-साथ कमल मोरारका जी ने आसाम के बारे में 10–1–91 को कहा:

"The Governor of Assam in his report dated 26-11-1990 addressed to the President of lndia has staled that the United Liberation Front of Asom (ULFA) has embarked upon an armed struggle for what they call as the liberation of Assam from the Indian Union and striving to set up an independent sovereign state. As many as 113 innocent people have been gunned down by the ULFA. Carrying on a campaign of vendetta, the ULFA activists have systematically killed police officers and political figures v,ho resist the achievement of their objectives. As many as 58 political workers have been killed during the last three years and 19 officials have been assassinated. The Govern or' also mentions that in the districts of Lakhimpur, Tinsukia and Dibrugarh, the ULFA activists have set up a parallel administration taking over the executive, administrative and judicial functions."

मेरे ख्याल से आसाम की अवस्था और जम्मू काश्मीर की अवस्था में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। उसके बावजूद आसाम के चुनावों की घोषणा की गयी और जम्मू काश्मीर के सिर्फ 80 लाख लोगों के गणतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया, उन्हें वोट देने से वंचित रखा गया। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुए, जम्मू काश्मीर में चुनाव नहीं हुए।

महोदया, बात यहीं शांत हो जाती तो शायद मैं बैठ जाता। पर महोदया, 25–2–91 को "प्रेजीडेंट रूल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की गयी है। उपलब्ध सूचना से यह संकेत मिले हैं कि हाल की घटनाओं और बिगड़ती हुई स्थिति से तमिलनाडु के स्थानीय लोगों के लए चिंता का विषय बना हुआ था। स्थानीय अपराधियों और अन्यों की हरकतों के कारण बढ़ते हुए हिंसक अपराधों के अलावा

अत्यधिक खलबली पैदा करने वाला पहले इस बात की व्यापक जानकारी देता था कि लिब्रेशन टाइगर्स आफ तामिल ईलम देश के कानून की परिधि के बाहर एक स्वतंत्र बल के रूप में कार्यशील है और उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसी शरणस्थलियां बना रखी हैं, प्रजन पर राज्य शासन का कोई अधिकार नहीं चलता है । वे रामनाथपुरम, तंजावुर, पुडुकोटाई और तिरुचिरापल्ली जिलों के कुछ भागों में एक स्वतंत्र प्रशासन के रूप में कार्य कर रहे थे । राज्य प्रशासन के एल०टी०टी०ई से प्रभावी ढंग से निपटने से आनाकानी करने के कारण उनकी हिंसक गतिविधियों में उलझे रहने तथा तटवर्ती इलाकों में आम लोगों को भयभीत करके अपना शासन चलाने तथा स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहन पाने के चलते भयावह स्थिति पैदा हो गयी थी । तंजावूर पुडुकोटाई और रामनाथपुरम तटों पर चोरी छिपे आने जाने वाली नौकाओं की व्यापक जानकारी के बावजूद राज्य पुलिस। तथा अन्य स्थानीय अधिकारी उस आवाजाही को रोकने में असमर्थ थे । तट पर उनके रुकने की कम से कम 40 जगहें थीं जिनका पता राज्य सरकार को था । इनमें से अधिकतर क्षेत्रों की प्रभावी शाली ढंग से न तो चौकसी की जा रही थी और न ही वहां सरकारी मौजूदगी का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा था । इन क्षेत्रों में अगर कुछ था तो वह एल०टी टी० ई की हुकूमत ही थी। इससे एल०टी टी० ई० की हरकतों की दीर्घावधि दुष्परिणाम हो सकते थे । आम नागरिकों के साथ इनका घुल मिल कर काम करना और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ाना, इनका एक महत्वपूर्ण पहलू था । एल टी०टी०ई० के सुव्यवस्थित गुप्त संचार नेटवर्क की मौजूदगी जिसमें एच एफ० और वी०एच०एफ० दोनों प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग हो रहा था । "दूसरा, तमिलनाडु जाने का तथा श्रीलंका में एल०टी टी०ई उग्रवादियों के प्रयोग के लिए शस्त्रों, गोला-बारूद, विस्फोटक पदार्थों को ले जाने का एक प्रमुख दल बना हुआ था। कुछ शस्त्र और गोला बारूद भारत के अंदरूनी भूमिगत रास्तों से ले जाते हुए भी पाये गये ।

एल०टी०टी०ई० तत्वों ने तमिलनाडु के राजनीतिक और आर्थिक तबकों के बीच मेल-मिलाप का व्यापक जाल फैला रखा था ।"

महोदया, उसके बाद "राज्य में कुछ अरसे से व्याप्त वातावरण से राज्य के अंदर और देश के अन्य भागों, दोनों में उग्रवादियों और अलगाववादियों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है, ऐसे सबूत मिले हैं कि पट्टाली मक्कल काची (पी० एम० के), तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट (टी० एन० एम), तमिलमन्नावर पेरावई (टी० एम पी) जैसे संगठन एल० टी०टी० ई० के उदाहरण से निडर हो करके अपना काम कर रहे थे । वे ऐसे संगठन हैं जो अलगाववाद की खुल कर एडवोकेसी करते रहे हैं और इससे वहां पर अलगाववादियों प्रतिनिधियों को बल मिलता रहा है । ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए असम के युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ने राज्य में प्रत्यक्ष रूप से अथवा मध्यस्थलों के जरिए एल टी टी० ई के साथ मिलने के लिए तमिलनाडु का, एक शरणस्थली एवं आधार क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया था ।"

महोदया, यह मेरी बातें नहीं हैं । यह सारी की सारी बातें इस मुल्क के गृह मंत्री की हैं, जोकि उन्होंने अपने भाषणों में इस सदन में हम सबके सामने रखी थीं । इतना लम्बा भाषण इनको पढ़ कर मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस वक्त इस भाषण को इस सदन में दिया जा रहा था, उस वक्त सारा विपक्ष चिल्ला-चिल्ला कर एक बात कह रहा था कि करुणानिधि की सरकार को तोड़ कर सरकार ने नरसंहार किया है, सरकार ने गणतांत्रिक अधिकारों की हत्या की है, सरकार ने लोगों का गणतांत्रिक अधिकार छीना है । मेरे दिल में भी ऐसी ही बात थी । मैं सोचता था, हो सकता है—दो साल पहले लोगों ने करुणानिधि सरकार को बनाया था, वह सरकार बनी थी और वह सरकार राष्ट्रपति शासन लगा कर तोड़ दी गई । उस वक्त मैं गृह मंत्री के इस मंतव्य के साथ सहमत नहीं था, पर आज मैं सौ फीसदी सहमत हूं । उसके पीछे तथ्य हैं, कारण हैं।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह आहलुवालिया]

महोदया, जम्मू-कश्मीर, असम और तमिलनाडु की बात हमारे सामने आती है। जिस वक्त करुणानिधि की सरकार को हटा कर वहां पर प्रेजीडेंट रूल लगाया गया, तो सारे विपक्ष ने 6 फरवरी को भारत बंद की काल दी और सारे भारत में जाकर भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल और सारे दलों ने मिल कर एक-एक प्लेटफार्म से भाषण दिये और कितना कुछ कहा। पर एक सुबोधकांत सहाय, जो उस वक्त के गृह मंत्री थे, उनका यह भाषण उस दिन अगर हम गलत न मानते, अगर हम वाकई सही मानते और उसका कोई रास्ता निकालते, तो आज इस मुल्क को इतना बड़ा नुकसान न झेलना पड़ता। आज वह नुकसान इस मुल्क को, इस थर्ड वर्ल्ड को हुआ है, जिसने 21 मई को मद्रास से 40 किलोमीटर दूर श्रीपेरम्बादूर में राजीव गांधी की नृशंस हत्या इसी एल. टी. टी. ई. ने की और धीरज दर्शक बन कर भारत की 85 करोड़ जनता ने देखा कि किस तरह यह उग्रवादी देशद्रोही, देश के टुकड़े करने वाले लोग किस तरह से एक संगठन बना कर खड़े थे और इस मुल्क के टोटे टोटे कर देना चाहते थे और जिस वक्त हमने उनके हाथों से सत्ता छीनी, सरकार ने एक कठोर कदम उठाया, तो इतनी आवाज उठाई, इतने पहाड़ तोड़े गये यह कह कर कि गणतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, गणतांत्रिक अधिकारों का खून हो रहा है। महोदया, यह वह दबाव था जिसने हमें मजबूर किया है कि सदियों तक हम इस पिछले चुनाव को भूल नहीं सकेंगे, भुला नहीं सकेंगे सदियों तक हम उस नृशंस हत्या को नहीं भूल सकेंगे। अगर चुनाव रोकना ही था तो सीधे-सादे उस जम्मू-काश्मीर के पहाड़ी लोगों का, क्यों रोका गया ? क्या आपको नजर नहीं आयी थी तमिलनाडु में ये घटनाएं ? आसाम में यहां कि वह चुनाव के समय वह शांत रहे और चुनाव के बाद जब सरकार बन गई तो लोगों का अपहरण शुरू हो गया। क्या उस वक्त आपको याद नहीं आया कि जब बिहार के मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सरेआम कहा कि वोट का अधिकार आपको जरूर है, पोलिंग बूथ पर आप जरूर जाइयेगा वोट भी डालिएगा, लेकिन रिटर्निंग आफिसर सर्टिफिकेट जनता दल के कैंडीडेट को ही देगा। ....(व्यवधान) यह सही बात है।...(व्यवधान) उस लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ इतना ही नहीं इससे ज्यादा धमकी दी और उसने कहा कि अगर गलती से किसी जनता दल के कैंडीडेट के सिवाय और किसी कैंडीडेट को अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो * । यह धमकी उसने दी।...(व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : महोदया, यह बहुत सीरियस चार्ज है और जम्हूरियत पर तो हमला है ही साथ ही साथ एक मुख्य मंत्री के खिलाफ यह बात कहना कि उसने कहा * * तो ऐसा चार्ज लगाने का अधिकार किसी सदस्य को किसी मुख्य मंत्री पर है या नहीं, आप व्यवस्था दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI -JAYANTHI NATARAJAN): I will like into the records and expunge any reference, that is. unparliamentary,.. *{Interruptions).* .

श्री राम अवधेश सिंह : यह क्या बात हुई इस तरह से कि कोई बोलते समय कुछ तो....(व्यवधान)

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): I am of the opinion that Shri Ahluwalia should not be taken seriously. . He . is . habituated to say anything. That his habit... *(Interrppt-ions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Everybody is a serious Member of this House. Everybody is serious. It is. you people who are not serious; that is why we lost Shri Rojiy Gandhi. It is you people '*.(Interruptions)* . . .

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अपने अधिकारों के अन्दर हूं।....(व्यवधान) मैं बाहर नहीं हूं।....(व्यवधान)

♦Expunged as ordered by **the Chair'**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Ahluwalia, please do not make allegations. .. *{Interruptions).. I* will get it removed from the records... *(Interruptions) ...*

SHRI CHATURANAN MISHRA: I told you, he should not be taken seriously'. . . *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MATI JAYANTHI NATARAJAN): Please sit down. . *.(Interruptions)...* Please sit down. . . *(Interruptions)..* . "Kindly excercise restraint Mr. Ahlu walia. .. *(Interruptions)..* .You cannot make allegations against other hon. Members... *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI

श्री राम अवधेश सिंह : 31 जनवरी, 1948 को भी भारत नहीं भूलेगा। महात्मा गांधी की हत्या हुई।.... (व्यवधान) और इंदिरा गांधी खुद प्रधान मंत्री थीं, उनकी हत्या हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, आप बताइये? तो इस तरह का चार्ज लगाना किसी दूसरे को.... (व्यवधान)

JAYANTHI NATARAJAN): Please sit down. . . *(Interruptions).* . .You cannot make allegations against hon. Members. I request you to kindly withdraw it. Otherwise, I will have to expunge it from the records... *(Interruptions)* ... Do not make allegations... *(Interruptions).*

SHRI CHATURANAN MISHRA: Is he withdrawing it?.. *.(Interruptions)* ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am ask ing him to withdraw it ... *(Interrup tions)* .. . Mr. Ahluwalia, please with draw your statement... *(Interrup tions) ...*

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): He must withdraw... *(Inter-rpi ions)...*

*Expungedas ordered by the chair

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): He must be asked to withdraw his statement... *(Interruptions) . ..*

SHRI S. S. AHLUWALIA: If you do not allow me to speak how can I withdraw my statement... *(Interruptions)* ...

SHRI SUKOMAL SEN: What is this,

*। महोदया, मेरा आरोप अपनी स्पीच में शुरू से यही है कि जिस वक्त तमिल-नाडु में.... (व्यवधान)

3.00 P. M.

Madam?. . . *(Interruptions). . .*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He cannot be allowed like this.. *.(Interruptions)* ...

SHRI SUKOMAL SEN: It is a shame on the Congress (I)... *(Interrup-tions*). ..

SHRI S. S. AHLUWALIA: They don't allow me to explain my argument . *(Interruptions).* . .Madam, I am serious. .. *(Interruptions).. I* am serious . . . *(Interruptions) . ..*

SHRI CHATURANAN MISHRA: He should withdraw it, Madam.. *.(Interruptions)* . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I will have it expunged from the record... *(Interrup-tionss) . . .*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, you must apologise... *(Interruptions)...*^ Member should be allowed to behave in this way in this House. What is this. ,\. *(Interruptions) . ...*

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): What is this, Madam? He must withdraw it... (*Interruptions) . ..*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He must appoligise. . . *(Interruptions) . . .*

SHRI S. S. AHLUWALIA: You ari not going to write my character certificate. . . *(Interruption)...*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I will never give you a character certificate. . *(Interruptions).* . I will never give you a character certificate... *(Interruptions)* .. Go and gel it from somebody else. . *(Interruptions)..*, There is no character at all. . . *{Interruptions)* .

SHRl S. S. AHLUWALIA: Madam, he is going out of the limit. . . *(Interruptions)* ... He is going out of the limit . . *(Interruptions).* . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Kindly with-draw those words. . . *(Interruptions).*

SHRI S. S. AHLUWALIA: No. My charges are based on some facts... *(Interruptions)* . . .

SHRI SUKOMAL SEN: What facts? . . . *(Interruptions)* ...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What facts?. . . (*Interruptions)* . . .

SHRI SUNIL BASU RAY: What facts . . . *(Interruptions)* .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Let me tell you, Mr. Ahluwalia,.. .*(Interruptions)* ... Let me tell you, Mr. Ahluwalia, you cannot make allegations against the Mem bers like this without bringing forward a substantive motion . . . *(Interruptions)* . . . You cannot just stand up here and make allegations in the course of your speech against the ether Members without a substantive Motion. . . *(Interruptions).* . .

SHRI S. S. AHLUWALIA: If you don't allow me to withdraw, what can be done? You are restraining my right also. . . *(Interruptions)* . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am only saying tint you cannot be permitted to make all gations against the other Members. . .*(Interruptions)* . . .

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am not making any allegation against any individual Member . . *(Interruptions)..* .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): It makes no difterence whether it is against one individual Member or many Members. In fact, it is much worse if you make allegations against other honourable Members . . .*(Interruptions)*. .1 would request you to kindly withdraw those words. I cannot permit you to make allegations against the other Members. For that you have to bring forward a substantive motion . . . *(Interruptions)* .

SHRI S. S. AHLUWALIA: Without explanation I cannot withdrow. . . *(In-ti rruptiofis)..* .Without explanation I cannot withdraw. Now, it is up to you, Madan. . . *(Interruptions).* . .

SHRI SUKOMAL SEN: He must with-draw. *(Interruptions)* He must be asked to withdraw...*(Interruptions)*...

SHRl GURUDAS DAS GUPTA: He must oiler an unconditional apology... *(Interruptions).* He must tender art un-qualified apology . *(Interruptions)...*

SHRI CHATURANAN MISHRA: He is not complying with your order...*(In-terruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: No Member can speak like this in this House .. ***(Interruptions)***

SHRI SUKOMAL SEN: He must be asked to withdraw. *'(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I cannot ask him to leave the House . (*Interruptions* I have asked him to withdraw his words. If he does not withdraw, I will expunge them from the record. (*Interruptions)*...

SHRI CHATURANAN MISHRA: Since the is not obeying the Chair, under protest we are walking out

\Ai this stage, some hon. Members left the Chamber

SHRI SUKOMAL SEN: Medam, you have failed to protect the rights of the Members. It is a shame on the Congress (I) *benches...(Interruptions)...* We are also walking out. *(Interruptions)*

[At this stage, some hon. Members left the Chamber.]

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह इनका स्पोक्समेन अखबार 'द हिंदू' लिखता है—

"'Burial of democracy.', Says all-party meet."

और जब तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो अखबार जो इनके भाषण रोज लिखते थे, उनमें लिखा गया कि गणतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है। सिर्फ यही नहीं, पेट्रियाट लिखता है—

"Basu urges the President to resign." और-तो-और मैं आपको बंगला अखबार "आजकल" का एक एडीटोरियल पढ़ सकता हूं, आनंद बाजार पत्रिका का एडीटोरियल पढ़ सकता हूं जिसमें क्या-क्या बातें लिखी हैं जहां राष्ट्रपति तक को खींचा गया है, गृह सचिव तक को खींचा गया है कि इस हत्या में उनका भी हाथ है।

तो महोदया, इन चीजों को सोचने की जरूरत है और जब इन तीनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन पहले लगे हुए थे और उस वक्त फैसला हो रहा था कि चुनाव होने हैं, लेकिन उस वक्त की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक तरफ तो सुबोधकांत सहाय ने कहा कि वहां ला एण्ड आर्डर सिचुएशन खराब है, विदेशी ताकतें बहुत सक्रिय हैं, विदेशी ताकतें किस तरह हमला कर रही हैं, स्थानीय लोगों के मन को इमोशनली जीतकर उनको भी अपने काम में इन्वोल्व कर रहो हैं। वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इधर चुनाव के मध्य ही चुनाव प्रचार जब चल रहा था तो उसी वक्त राजीव गांधी की नृशंस हत्या की गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है, जिन्होंने उस वक्त कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाना इन लोगों के गणतांत्रिक अधिकारों का हनन होना है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर अंगुली नहीं उठाई। मैंने उस प्रेशर ग्रुप पर अंगुली उठाई है, जो ग्रुप इन अपराधी तत्वों का, इन देशद्रोही तत्वों का, विदेशी ताकतों के हाथों बिके हुए तत्वों का समर्थन कर रहा था और एडवोकेसी कर रहा था, जिसके प्रमाण गृह मंत्रालय में थे और गृह मंत्री ने इस सदन में दिए थे मैं उनके माध्यम से बोल रहा था।

महोदया, हमारे मुल्क में रास्ते अनेक हो सकते हैं, सोचने की बात अनेक हो सकती हैं। नेहरू जी ने कहा—

"It is the civilized approach to a problem about which people differ, the non-violent way of dealing with it. To crush a contrary opinion forcibly and allow it no expression, because we dislike it. is essentially of the same genius as cracking the skull of an opponent because we disapprove of him. lt does not even possess the virtue of success, The man with the cracked skull might collapse and die, but the suppressed opinion or idea has no such sudden end and it survives and prospers the more it is sought to be crushed with force. History is full of examples'

THE VICE-CHAIkMAN (SHRIMATI IAYANTHI NATARAJAN): How much longer will you take?

SHRI S. S AHLUWALIA: I have just begun.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATl JAYANTHI NATARAJAN): You have already taken 40 minutes and the time allotted for Congress party is one hour and twenty minutes.

SHRl S. S. AHLUWALIA: I am not taking the party time. I have moved this Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) No separate time has been set aside for the Mover. Anyway how much more time do you want I am just asking.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am con-eluding.

महोदया, इस अध्यादेश का रोज-रोज निकलना और इसका दुरुपयोग होना, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सिर्फ यही कह देना कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के बगल में रहते हैं या पाकिस्तान की बोर्डर उसके साथ मिलती है और इसलिए वहां पर जो अपराधी तत्व थे या जो आतंकवाद था उसको दबाने का सही तरीका यही था कि वहां चुनाव न कराए जाए। यह गलत है। जब हमने 545 सीटों में से 528 सीटों पर चुनाव करा दिए तो हमें क्या फर्क पड़ता था वहां छह और सीटों पर चुनाव कराने में ? हमें सोचने की जरूरत थी। पर हमने सोचा नहीं और आज भी हम नहीं सोच रहे हैं। आज भी फिर उस अध्यादेश को लाकर, उसमें अमेंडमेंट करके उन ताकतों को और मजबूत करते हैं. जो आहिस्ते-आहिस्ते हमारे अध्यादेशों के माध्यम से, हमारे अमेंडमेंटस के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से हमारी ही जनता के अधिकारों का हनन करते जा रहे हैं। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। यह सब कुछ सोचते हुए और इन सब चीजों पर अपने मन में विचार करते हुए मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AF FAIRS AND THE MINISTER OF STA TE IN THE MINISTRY OF LAW, JUS TICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGA-LAM): Madam Vice-Chairman, I beg to move:

That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration."

Madam Vice-Chairman, the Bill seeks to replace the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1931 (Ordinance No. 2 of 1991) which was promulgated by the President on 18th April, 1991. In accordance with the provisions of svb- section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India recommended the issue of a notification by the President on 19th April, 1991 calling upon all par-liamentary constituencies other than those in the State of Jammu and Kashmir to elect Members for constituting the Tenth Lok Sabha. The Election Commission recommended issue of a notification separately, in due course, in respect of the parliamentary constituencies in Jammu and Kashmir. The Election Commission bad made this recommendation because according to the Commission, major political par-ties bad expressed the view that the situation at that time was not conducive to the conduct of free and fair eiections in Jammu and Kashmir and that special security arrangements were required to be made before elections could be held there. The Commission accordingly proposed fixing up of a separate programme in due cotirse for elections to the parliamentary constituencies in Jammu and Kashmir.

Under Section 73 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission is required to notify the names of the Members elected from the different constituencies and upon (he issue of such a notification the House concerned shall be deemed to be duly constituted. In section 73, there is provision only to exclude the results in respect of those constituencies for which poll could not be taken on the date originally fixed or where the time for completion of the poll had been extended by the Election Commission. No other exception exists.

Therefore, in order that the President could issue a notification under Section 14(2) calling upon all the constituencies, except those in the State of Jammu and Kashmir, to elect new Members on 19th April, 1991 and in order that this process could get completed with the issue of 'due constitution' notification by the Election Commission under Section 73 it was necessary to override Section 73 Of the Representation of the People Act, 1951 suitably, to enable the Election Commission to issue a 'due constitution' notification under that Section without taking into account the parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir. As the matter was urgent and as- the Parliament was not in ' session, the Representation of the People

(Amendment) Ordinance, 1991 was promulgated by the President on 18th April, 1991. Thereafter, the Presidential Notification, calling upon the constituencies other than those in the State of Jammu and Kashmir, was issued on 19th April, 1991. As the hon. Members are aware, in the past similar Ordinances were promulgated in the cases of Punjab and Assam.

The holding of elections to the Parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir has not yet been decided. Further, in order to ensure the continued availability of the legal basis for the action taken and to be taken, it is necessary to replace the Ordinance by an Act of Parliament. Hence, the Bill is before the House. I would request that the Bill be taken into consideration.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The Statutory Resolution and the Motion for consideration of the Bill are now open for discussion. Shri M. C. Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE) (Maharashtra): Madam Vice-Chair-person rise to support the Bill.

Madam. 1 a proud to be an Indian citizen. In fact, since some of us oelieve in rebirth if I were to be asked where I would be reborn, I would unhesitatingly say that I should be reborn in India.

And where in India? Unhesitatingly, I would say in Bombay because Bombay is a mini-India. Now, why do I say that? I say that because it is a very free and open society Ours is a very mature democracy. Nowhere in the world do you find such diversity, such variety, such conflicting interest in matters of religion, in matters of language, in matters of region and in ethnic matters. It is all right to talk about USA. They have one language. They have no problems which this diverse mjulti-cultural, multi-religious, multi-communal, multi-ethnic and multilingual society of India presents. The challenges art really very serious and the 198 RS—8 time has come for us on occasion like this to go into a little detail on each of those challenges. Despite this diversity what India has achieved, has not been achieved in the rest of the world. We are a developing nation. Despite our technological progress and advance a large section of our population lives below the poverty-line. They suffer constantly from hunger and want, occasionally from fear as well. This is not a very happy environment for the human rights to which a reference was made by my friend Mr. Ahluwalia. Despite all these things, India is one counlry where there has been a peaceful change through ballot. And it is a matter of great pride. In fact democracy is everywhere in the world including Pakistan, Bangladesh, Burma—take any country in the region,—is completely broken down. It is only in our country that democracy has not only survived but thrived. It is indeed a matter of some regret that we had to go in for general elections particularly in a matter of 16 months, since we voted last. We had to go without a notification coming under Section 14 and 30 of the Representation of the People Act for the State of Jammu and Kashmir. Nobody feels more sorry than myself for a situation where people are deprived of their right to vote. But this is unavoidable and we as the legislators who have to uphold the rule of law—since there is no provision in Section 73 we have just to uphold that rule of law and to comply with the provisions of law—support this Bill. But, this Bill is also an opportunity to see why one State has been kept out of the election process altogether when the General Elections were announced for the Tenth Lok Sabha. I was all amazed to hear my friend, hon. Member Shri Ahluwalia, saying that we should look at Kashmir as adjacent to Pakistan. That was not the only thing. Bengal is adjacent to Bangladesh. Nobody looks at it from that angle. But, the real point is that the basis of any democratic elections is that it has to be free and fair, and we must, as champions or liberty as champions of human rights and as champions of freedom, ask ourselves and give an honest answer whether there are conditions prevalent m Kashmir, the valley of

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

Kashmir particularly, under which we **can** have a free and fair mandate of the people of that region, whether it will reflect **a** true verdict, a popular verdict and a free verdict of the people of that valley. The question, if I may put it in contrast is, whether the ballot will succeed 01 the bullet will prevail. Whatever one may say, it is a matter of regret that some of us who have been repeatedly raising this question of Kashmir for years and years, our protestations voiced in defence of the people of Kashmir have at all times, fallen on deaf ears, no matter what the Government was. Things have gone from bad to worse

It is unfortunate, that in the last 16 months, especially in the first 11 months, when we had a Member from Jammu and Kashmir as our Home Minister, the things did not improve. In fact, things worsened. To solve any situation of this kind, the measures can be divided into 3 compartments. You have the administrative measures, you have the political measures and you have the development measures, I am in entire agreement with what hon. Member Shri Ahluwalia said that democracy was destroyed and destroyed. I am not here to apportion the blame, I am only recounting history. It was destroyed the day when the Jammu and Kashmir Assembly was dissolved. Members of the Assembly, whether they were Congress Members, whether they were National Conference Members, as long as they were Members, they proudly said that they belonged to the Congress or such and such parties and they could say this. The moment the Assembly was dissolved, they became orphans and started shouting Pakistan Zindabad' along with the other militants. That is a matter of shame for us because right from Rubiya kidnapping episode right from putting Shri George Fernandes in charge of Kashmir affairs and Shri Mufti Mohammad on the other side, you find a tremendous slide down in the democratic position. I will wind up my speech giving practical solutions under each of the three heads, namely, the administrative head, the political head and the developmental head But, before that I want to satisfy the House that if any. one has a perception that in today's climate in the valley, a free and fair election, is possible, such a perception is not only a distortion of fact, but it verges on perversity. It cannot be forgotten at all that, today, Pakistan is waging a war by proxy against India. Nobody is happy. We do not like the Army being there in any part of the country at any time. I do not think that is our creed, or, that is the way India behaves. Our country has been, as I said, a democratic society We have our Army to fight foreign invasion. We rarely use it In spite of that, we have the Army stationed in Kashmir for such a long time. We do not like it. But it is not a question of our liking it. It is a question of meeting a situation. If anybody feels that Jammu and Kashmir is an ordinary problem I am not prepared to take it

As I said, this is a problem of the unity and integrity of the country. Madam, this one thing, the unity and integrity of the country is totally non-negotiable. No matter what sacrifices we have to make, we will make them, to preserve the unity and integrity of the country. The doctrine of autonomy, the doctrine of self-determination, has no place at all. India is one. India is indivisible. Many of us are prepared to give our last drop of blood to keep it united, to keep India one.

Madam, I am going to devote a greater portion of my speech to some of the allegations which are now current not only in Pakistan but in the rest of the world also.

[The Vice-Chairman, (Dr. Nagen Saikia,) in the Chair]

Though this Bill is simple, I want to take this opportunity to clarify the entire picture. On the one hand, you have a war- like situation there. I do not have to give the figures. The figures are there. Increasing militancy. Increasing seces-sionism. Activities fomented, aided and financed by Pakistan. The training of **men** and supply of arms, sophisticated arms, by Pakistan is a matter which has **now** been well-established.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): Even manpower.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: In fact, it has been accepted even by those who care to know the correct position. On the one hand, you have this picture and you cannot possibly meet this kind of an aggression Of coarse, it is not an open war. But this is what makes it far more difficult That is why, I feel that anybody who thinks that today, there would have been free and fair elections is entirely in the wrong. What is the situation today? Well I do not have to mention it We have had the kidnappings of some Israeli citizens one of whom was shot dead. Then the two Swedish engineers got away with some difficulty and with good fortune. Mr. Doraiswamy is still there. There are a number of killings. It is indeed a matter of regret that as a direct result of all these activities, what has happened is that developmental work in the valley has come to a dead halt. Today, you cannot build even a furlong of road in Jammu and Kashmir where roads require to be repaired regularly because of the very heavy snowfall in those areas.

SHRI YASHWANT SINHA: The Moghul Road has been abandoned.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE; Now, I want to give a package. The Government is talking of a package. But nobody reads what we say here. It remains fhere as it is. May be, after some time, somebody reads it and tries to get the idea.

Today, the administration is totally paralysed there. There is no administration. Somebody had taken it into his head that if you do not have Kashmiris in the administration of Jammu and Kashmir, if you have somebody from Maharashtra or from Tamil Nadu or from Bihar, the administration would work better. But is that the way to go about the administration at all?

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) बिहार में क्या एडमिनिस्ट्रेशन हैं ?

श्री मुरलीधर चन्द्रकांत भंडारे : वह बोलते हैं । (व्यवधान)

SHRI A. G. KULKARNI; He is defeated in Bihar. There is no administration.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: He is not defeated. His election has been countermanded. *(Interruptions).* I am glad that my hon. and veteran senior is, for a change, taking note of what I am saying.

SHRI A G. KULKARNI: 1 understand what you say. My only submission is Bihar, and U.P., these are the only two States which are a drag on this country.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I don't know how it will be if you put them in sopore or Badgam, it is only a theory.

Therefore, the first requirement is that you tone up the local administration. Look at what has happened. *(Interruptions).* Let me deal with the situation in Jammu and Kashmir. Today, there are no journalists in the valley. All of them have fled away from the valley. And what is worse? Mr. Minister, will you listen to some of the things and carry them to the Home Minister? This is very very important. What is worse is, both the Home Minister and the Foreign Minister should have been present today because this is the only occasion when probably in this session we are going to discuss the serious question of Jammu and Kashmir.

As I was saying, after the shooting down of the Director General of Doordar-shan, the Government itself has moved both the broadcasting stations of All India Radio and Doordarshan. This cannot be understood at all. It clearly shows, to what extent we are panicking. I think the first thing that they should do is that they must restore these broadcasting stations of All India Radio and Doordarshan back in the valley. We must show that we are in a position to protect these broadcasting stations.

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare] I will tell you something else. Mr. Vice-Chairman, Sir, you are my esteemed colleague in the press *council we* have expressed our desire that we want to hold a meeting of the Press Council in Srinagar, and the Home Ministry is not permitting us. We will go there. Why? We do not need security. We will go there at our own risk. So, Mr. Minister, convey it to the Home Minister that let the Press Council meet. Even if two or three of us have to be killed, it does not matter. That will be a small price we will pay to show to the rest of the world what India stands for. So, on the one hand we have the serious situation and if it is understood that there is not even a gost of a possibility of free and fair election because it would have been the vote of the gun, then we must support this Bill. It becomes the bounden duty of every Member of parliament to uphold the law. There is a lacuna in the law Which is really not a lacuna at all. That is deliberately kept because India is one and you will have one election. There have been only two exceptions in the past to the section 73. In 1985 when we had the general election we could not have the elections in Punjab. We passed Act No. 9 in 1985, exactly with similar words for the State of Punjab. It is a matter of great satisfaction that in 1989 we had elections in Punjab and we will have elections in Punjab very soon, sooner the better. And we will prove that there is democracy-vibrant, very alive and very effective. In 1990 we had the same problem in Assam. Of course, the reason given was that the electoral rolls were not complete. But it is only a new device.

There are precedents. It is a well-established device and, in a country of our diversity, as I said, where there are convicting interests when it is trying to build itself, in 40 years it has come to be a secular, free, open, democratic society. I know, today we have challenges—we have a challenge from fundamentalists, we have a challenge from all kinds of religious fundamentalists—but let me express my hope, and the House will share with me that we have opted for a modern and egalitarian society where there is no place, no room, for fundamentalism, or obscurantism which is even worse. But this is the last-ditch battle which religious fundamentalism and obscurantism is fighting against nationalism, is fighting against an egalitarian society, is fighting against a modern society, and I have no doubt in my mind—and the House will share my hope—that these forces of fundamentalism and obscurantism will be vanguished.

SHRI SIKANDER BAKHT: You are pointing at me... *{Interruptions)...*

SHRI MURLIDHAR CHANDRA KANT BHANDARE: No, I am not poin ting at you. ... *(Interruptions)* _____ No, no, it is not my style. If Sadhvi were there, probably, I would have done it.. *(Interruptions)....* I am sorry.

But this is a very serious thing to which I want the House to give its attention. Please don't be disheartened because what will prevail in this country ultimately will be the nationalism, the secularism, the spirit of tolerance which pervades through the country. In fact, it is that air which we breathe in and out, and what will be finished are these poisonous gases which are temporarily let loose and are affecting the minds in some parts. But in order to see what is rational, what is national, what is secular and what will promote and protect human rights, we will have to pay a very, very heavy price. We will have to be eternally vigilant and we should not show any respite in our efforts to support that which has been so fundamental, I mean, our Constitution. This Constitution, you will find, has been the longest Constitution till the Yugoslav Constitution overtook it. Particularly, about the Preamble to our Constitution, an eminent Professor of Cambridge has said that it is the most beautiful poem he has read—a poem for all human beings, promising justice, promising equality of opportunity and status, and liberty and fraternity. That is the spirit which pervades our society.

And, therefore, I have no manner of doubt at all that it is only a short-lived thing that we do not have elections in any part of the country; it is only a passing phase. The permanent phase is that we

will have a peaceful transition, we will have a silent transformation through the ballot, eliminating the bullet everywhere in the country. When I am on this point, I must come to another thing which has been said even in this House, and I want to enter a strong caveat. Well, there is a systematic propaganda. One of the problems is, of course, that they train people and send them across the border. But the most important is the propaganda and the disinformation which is let loose by Pakistan not only in Pakistan but in several other countries, particularly in the USA. Now I want to meet this. Then they harp on the same theme of the violation of human rights, atrocities committed by the military personnel in Kashmir. It is a matter of regret that while we remove our station, the broadcasting station from Srinagar to Jammu—there was a question which I asked—there is a radio station which has been started by Pakistan for the valley. This the difficulty. Now I will deal with this aspect of it.

There are a few things which are necessary for promotion and protection of human rights. The first requisite is that our free, open society, democratic society must be rooted in the rule of law, and I am proud to say that our democracy is entirely rooted in the rule of law so much so that an ordinary man totally abhors any infraction of law. It is not as if the army personnel are not taught what they should do and how they should meet the situation. In fact, it is not publicised that action has been taken against several army personnel in regard to the complaints against violation of human rights of the residents in the valley. Action has been taken, but. unfortunately, what happens is that under the Army Act the proceedings of the court martial cannot be published. The time has come when in matters dealing with human rights at least those proceedings should be published so that there will be security in the hearts and minds of the people that if anybody ever tries to fiddle with human rights he wTA be punished harshly. There is a continuous propaganda, and some of TO also fall a prey to it. You find it being discussed even in the U.S. Congress, the House of Representatives, the Senate. I am very happy that only last month they rejected all these allegations against us. 1 must express, and the whole House will join me in expressing, our sincere thanks to the U.S. Congress for realising that the human rights are fully protected in India and that the insidious propaganda has no place.

But at this stage I do want to refer to a report which *has* come only two or three days earlier. Well, Sir, you are a part of the Press Council, and I am also a Member. We had an occasion to form a small committee. Ultimately two members did the job. Originally there were three mem bers. Mr. B. G. Verghese and Mr. Vikram Rao have given their report. They went into the case, each case individually. I must put their findings on record because this human rights problem is going to crop up again and again. I have read about the Amnesty report in the morning because my friend Mr. Yashwant Sinha was showing it to me. I will get it in a day or two. They normally send it to me. I do not know why it has not yet come to me. I will certainly give it to you. 1 will read a few findings:

"Human Rights Organisation in India and abroid have reported on Kashmir from time to time in addition to the international press. Human rights groups have a constituency and in the usual manner of adversarial reporting exhibit a petfectly understandable bias against the establishment and in favour of the alleged victims who are seen as the underdog. Human Rights groups, however, need to be more investigative and chect: all sides more carefully before they come to firm conclusions, which they then proceed to publicise. In the Kunan case, great damage was done by the preliminary report of the District Magistrate, Kup-wara.

Asia Watch in its May 1991 'Kashmir Under Siege' makes the cardinal error of equating a legitimate, sovereign Government with faetless terrorists and

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

armed infiltrators guided by their mentors across the border. Insurgency or civil disorder confers no right on any Government to kill indiscriminately. But the Indian armed forces and paramilitary formations are bound by the laws under which they operate, the Constitution, and the jurisdiction of the Courts."

That is why I said they were rooted in the rule of law.

"There have admittedly been errors and excesses which cannot be condoned. Action has been taken and the guilty punished in a number of cases and so there is no justification for the belief that the Government of India or military| security force commanders have turned a blind eye towards gross misconduct or excesses by persons under their charge. There is certainly absolutely no warrant for the US Congress to advice the American Administration that the training the US provides India's armed forces must stress adherence to internationally recognised standards of human rights. This is a gratutious insult by a Congress that irresponsibly supplied the arms that were diverted by Pakistan from Afghanistan to terrorists in Punjab and Kashmir who in turn have been responsible for brutal killings on an unprecedented scale.

Human Rights violations are bad. Even one extra-judicially killings or a single rape is one too many—and it will never be condoned and it will always be punished.—Yet any judgement on these matters, which are more a product of human failure or frailty and emotional stress rather than of deliberate State policy or connivance, should be seen in the context of the scale, spread and intensity of terrorist/ insurgency operations and official responses, the number of security forces deployed and the number of incidents that might on investigation be reasonably listed as human rights violations. This is not to extenuate abuses, but to ensure a sense of proportion. It may be of some interest to look at Amnesty International's latest report on human rights in the **U. k** with reference to Northern Ireland"—

And they referred to that.

I may say that what they have ended with is a matter...

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, it should be laid on the Table of the House lt it an interesting report.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: It is a long report and I do. not want to go into it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The Press Council Report cannot be placed on the Table just by a Member here.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, may 1 read some of the more important findings. I want an approbation of these findings from the entire House without an exception.

'The Committee is firmly of the view that reports of human rights excesses against the Indian Army in Kashmir have been grossly exaggerated and invented. Some excesses have taken place, but these have been enquired into and action taken against those found guilty.

Then they go on to the two more serious allegations against the Army *viz.* the so-called Dudhi killings and mass rape of women at Kunan Poshpora and say they are without foundation. They are entirely baseless and are a figment of imagination.

"The Kunan rape story on close examination turns out to be a massive hoax orchestrated by militant groups and their sympathisers and mentors in Kashmir and abroad as part of a sustained and cleverly contrived strategy of psychological warfare and as an entry point for reinscribing Kashmir on the international agenda as a human rights issue. The loose ends of contradictions in the story expose a tissue of lies by many persons and at many levels.

The women of Kunan Poahpora have been tutored or coerced into making statements derogating their own honour and dignity. This cruel exploitation of simple women through demeaning self-abuse is itself a deplorable human rights violation.

Although the Committee's terms of reference pertained exclusively to the Army it has reviewed the functioning of the para-military forces in passing as anti-terrorism and counter-insurgency operations are indivisible and the militants are operating under an overall, unified strategy.

Generally speaking, the procedures regarding inquiries into excesses need to be speeded up and made more transparent and the findings published without delay."

He has ended by saying and 1 will read that also-

SHR1 YASHWANT SINHA: WilL you yield for a minute?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Yes.

SHRI YASHWANT SINHA: I think the report which the hon. Member is reading is a very important document which has been chronicled by the Press Council of India. This gives a total lie to all the so-called human rights violation stories, rumours and inventions which are appearing abroad. So I entirely support the point that he made and the whole House should endorse this. May I also request the two Ministers who are present here that at some point of time, very soon they should arrange to have this report laid on the Table of the House so that we can all share it? Mr. Bhandare is a Member of the Press Council and he is having access to the report. Mr. Vice-Chairman you are also a Member. But we do not have access to this report yet. May I request the Ministers who are present here to assure the House that they will take the earliest step to lay it on the Table of the House?

THE VICE-CHAIRMAN (DR NAGEN SAIKIA) The Government will take **note** of your suggestion.

SHRl MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I have always been grateful to my friend for a very solid, very vital and very emphatic support **ON** such crucial issues.

"Most of the charges levelled against the Army are anecdotal and not properly investigated. Human rights organisations and the media play a valuable watchdog role but have an obligation to be far more rigorous in piecing together information and publishing what might pass for hard findings. The mere say-so of alleged victims and propagandists can only be treated as such and suggest a cause for inquiry, no more.

The Indian Army has broken new ground in taking the bold decision to throw open its human rights record to public scrutiny through the Press Council of India. Few armies in the world would invite such an inquiry. The Indian Army has cooperated in this task. And it has. all things considered, emerged with honour."

I place this report on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKTA) It has to be done by the Minister.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Now I will come briefly to my suggestions.

SHRI A. G. KULKARNI: May I know whether the report is laid on the Table?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: My friend who went on saying that I should lay it on the Table of the House

SHRI A. G. KULKARNI: He said "not laid." You give it to me. I don't mind.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The Minister has to authenticate the report and only then it can be laid on the Table.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO IADHAV (Maharashtra): You lay it on the Table of Mr. Kulkarni.. .*(Interruptions)* ...

SHRI MURLIDHAR CHANDRA-IKANT BHANDARE: Sir having answered all these questions, I now wind up by making some humble but positive suggestions. It must be remembered that by far, an overwhelming proportion of the masses of the Valley are in national mainstream. Make no mistake at ali. I have some experience and I know how strongly they feel about India. We must strengthen this spirit of nationalism. I have a suggestion that every engineering college and every medical college should create two seats, free, for students from the Valley. I am referring to engineering and medical colleges as an illustration. This could be done in the case of HTs or important colleges, prestigious colleges, also for prestigious courses. And they should get free education. If every year 200 or 300 students go for courses in the most prestigious institutions, the best talent of the valley is sent outside. They are thrown open to the culture, unique culture, of the country. I think when they go back—whether for vacation or for their preparations or for some other purpose it will create a tremendous difference in public opinion.

The administration, as I said, must be tightened up. But it must be done more with the people of the Valley or Jammu and Kashmir than by sending people from Maharashtra and Tamil Nadu and other places. They have their limitations. They do not follow their language. They are not acquainted w th their customs and habits. That kind of a thing does not work. As I said, please restore broadcasting stations. Please allow more people to go **there even though** it may mean a little **more** security for them. Please start your developmental programmes by involving the people. If you find that a programme cannot be worked out by the SDO or the Executive Engineer, you call the head of the village and entrust it to him. And everybody will be paid at the end of the day provided he has worked. But developmental activities must be started immediately.

On the political process, as I said, what lies at the heart of democracy is discussion and debate. All the time you must go on discussing and debating with people who count, people who have the requisite support, leaders who have got the requisite support, and match it with your efforts. It should be a carrot and stick policy. Not that you silence your guns. The guns may be necessary. But at the same time, do not foreclose all your options for a negotiated settlement within the framework of our Constitution. Send more and more people. Send a team of Members of Parliament. in this connection, there is a point which I have missed Only last month, the President of the Pakistan Senate, with ten Senators, went to the USA and called on all the high dignitaries. They are propagating their things against us on Kashmir. And we are not effectively combating that kind of propaganda in the international field. I have already written a letter to the Prime Minister and to the External Affairs Minister to take an initiative. We can have very very good representatives **like** Mr. Yashwant Sinha to do such a fine job.

4.00 P.M.

SHRI YASHWANT SINHA: But both the Ministers are talking to each other *(Interruptions).*

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: That will never stop. That is an eternal tragedy. That is what I started by saying that nobody is going to read. But I am only doing my duty to place it on record. *(Interruptions)* .

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): The hon. Member does not know where the tragedy will end *{Interruptions).*

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, all in all, I can end up by saying that we will pass this Bill as a matter of compulsion with lot of anguish and reservation. But in the process, we assure the whole world that India will continue to be a lighthouse of democracy for other nations to chart their course towards independence and freedom.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, when elections to the Tenth Lok Sabha were held, elections could not be held in Jammu and Kashmir and as a result, this Bill has come to replace the Ordinance. Sir, I rise to support this Bill but with a heavy heart because democratic process could not take place in Jammu and Kashmir under compelling circumstances. Sir, today also, when we are discussing this legislation, it is not just a question of legislation. It is a question of the interal situation of Jammu and Kashmir. How can we tackle it properly? How can we reach a solution? I would have been glad if the Home Minister could have been present in the House to listen to deliberations of the Members so that the Government could know how the Members are thinking on the subject. At least, I would expect the Ministers who are present to listen to what we say. Sir, the problem is, how democracy was killed in Jammu and Kashmir. Many things have been said. Now, it is very difficult to go into the past and it is not relevant to do so. But I would only like to say a few words only to put the record straight.

Democracy was killed in Jammu and Kashmir not today or yesterday. The process started much earlier and it came to a head when Farooq Abdullah Government was dismissed, a puppet Government was installed and when Delhi was ruled by the Congress Government. Perhaps that started a chain reaction of the alienation of the local people who felt that it is Delhi and not the people of Jammu and Kashmir who will decide the fate of that border State. Sir, border States have always some problems. You come from a border State. You are aware about the problems *ot* your own State. You are aware of the problems of the States in the northeastern part of the country and in Jammu and Kashmir where a major part of the population belongs to minority, when a part of Kashmir is occupied and when Pakistan has some vested interests in creating trouble in Jammu and Kashmir, instigating some elements to create some problems, in such a situation, whatever complexion the *Government* of India might have, it should have been much more careful in tackling the situation in Jammu and Kashmir. Unfortunately, that has not been done. In reckless pursuit of partisan political end, the Kashmir problem was tackled in a manner which was not desired at all and the result is very clear now. Everyone of us is experiencing what is happening in Jammu and Kashmir. Sir, Pakistan has from the very beginning raised the problem of Jammu and Kashmir. It has raised it in the international fora. The Simla Agreement was signed, but Pakistan never showed any sincerity to follow the spirit of the Simla Agreement. Again they tried *to* internationalise the situation. We should have been much more careful at that time, but that could not be done. In the present situation we will have to pass this Bill and we will have to wait for a situation when it will be congenial for holding elections. That is most unfortunate for us, most painful for us. We will have to wait for it. But how long, is the moot question today. Sir, the new Government has come. I would like to know from the hon. Minister what the outlook of this Government is towards the problem of Jammu and Kashmir and how they want to solve it. The previous Government led by Mr. Chandra Shekhar which was proposed up by the Congress Party could not take a proper view of the jammu and Kashmir problem nor the problem showed any sign of a solution when V.P.

[Shri Sukomal Sen]

Singh was in power because it had been sliding down and down. Now the reports that many terrorists are being arrested, they have been brought to book, they are put in jail and many of them are confessing how Pakistan has been trying to motivate them, to train them and to instigate them and many are trying to change the path also, are appearing in the press. It is a good sign, but a problem like this cannot be solved only by the Armed Forces. Some other means, some political processes are necessary. And how and in what way the Government is contemplating to follow that path is the moot question today.

Sir, I would like to say that many questions have arisen about the violation of human rights in Jammu and Kashmir. I very much condemn the deliberations of the US.. Congress which wanted to interfere in our defence affairs and criticised the Indian Army for violating the human rights in Jammu and Kashmir and Punjab. Whether human rights are violated in Jammu and Kashmir, how far they are violated, that is a different question. But what right has U.S. Congress got to interfere in our own affairs? What had the U.S. Congress done when human rights were violated in El Salvador, when human rights were violated in South Africa and when human rights were violated in Vietnam? When the Mylai massacre was committed by the U.S. Army, at that time their conscience did not prick. But now on the issue of Jammu and Kashmir, it has done so. Mr. Bhandare has elaborately quoted the findings of the Press Council. What I would like to say is, while we condemn the interference of the U.S. Congress, at the same time I would like to caution the Government that our Armed Forces, out paramilitary forces, should definitely practise restraint in this matter. Any deviation, rape of a single woman, killing of a single innocent person, can vitiate the whole atmosphere. They have spoiled the gains which we have achieved. A good sense is **com**ing down on a section of the people of Kashmir that Pakistan has let them down and that joining Pakistan is not a solution for them, their fate lies in India—this sense is gradually coming up. At this time any little violation of human rights in the State of Jammu and Kashmir may create problems, it can start the process in reverse direction and people will feel frustrated. That is why I would caution the Government that they should restrain the Army and they should very much take care that the Army does not commit any sort of violation of the human rights or any sort of excess in the State of Jammu and Kashmir. Not that we will compromise with the terrorists, not that we will compromise with Pakistan for sending their terrorists. But at the same time we should practise restraint Sir, at the same time I would like *to* say that there are many problems that the Kashmiri people face. Tourism, which is the mainstay of Kashmir's economy, is totally shattered. Next come the fruit growers, the growers of apples and other fruits. This is another big industry in Jammu & Kashmir. The fruit growers and sellers from Kashmir are complaining that the present Government under President's rule is not taking any practical measures to safeguard the interest of the fruit growers and fruit sellers and as a result in competition with other States which also grow fruits, these fruit growers and sellers are suffering a lot. Had there been a popular Government, that Government would have looked into the problem and enabled the people to grow and sell fruits. The carpet industry, the local carpet industry, which is unique in India, is suffering. The shawls that are pro duced in Jammu & Kashmir and sold outside Jammu & Kashmir are also greatly suffering. At least on this score the Government under President's rule can see to it that these local industries do not suffer and even with these constraints, even in this difficult situation, they survive and they feed their own people. But unfortunately the local administration is so much bogged down in fighting the terrorists, in booking them and in countering them that they find little time to look into the

problems of the local people who are other wise innocent. Take, for example, the Government employees. A few weeks back, they went on a prolonged strike because so many of them were arrested in connecteion with some terrorism. Now, their complaint is that their economic demands have not been met. Sir, when the Fourth Pay Commission's report came out the State Government employees all over the country demanded parity of scales with the Central Government employees and in most of the States this has been done. But in Jammu and Kashmir the State Government employees are still lagging behind and are perhaps the lowest in the whole of the country. The employees' complaint is that there is President's rule and even then their small economic demands have not been met properly and in the complex situation the administration is so much busy with the army fighting the militants that they have hardly any time to look into the economic problems of the Government employees. Sir, without Government employees the Kashmir Government cannot be run. If the entire Government employees fall prey to terrorism, it is impossible to do any work in the State of Jammu & Kashmir. Sir, these problems are there. Sir, there are several other problems. Of late, Kidnapping has taken place, of one Mr. Dorai-swamy of I.O.C. Ltd. Too much need not be said about it because negotiation for release is in the final stage. I am not going to refer to that. But I would like to ask, Sir, how people will work there. Some Members were saying that the development work should continue there. How, unless the Government is determined to protect the people? Sir, three months back a top official of the HMT had been kidnapped and killed. Only two days back one L.I.C. officer was killed. Now Mr. Doraiswamy has been kidnapped and this is the 17th or 18th day of his being kidnapped and is not being released. Sir, if employees and officers of the public undertakings such as banks, L.I.C, I.O.C.—without which you cannot do any developmental work in the Valley or in the State—cannot function there, how can the developmental work continue?

And the Government is miserably failing in protecting the officials of the Government and the public sector who want to discharge their duties in the Valley in exremely difficult conditions. The Government is failing to protect them. And unless the Government gives them full protection, it is not possible to continue the developmental works in Jammu and Kashmir. And this is what the terrorists want. The terrorists want to show that the Government of India is not interested in continuing any developmental works in the State and thereby they expect the people to get alienated. The Government must beware of this aspect. This is a problem which the Government should not neglect.

Before I conclude, 1 like to mention that thousands and thousands of migrants have come to Jammu and other parts of the country. So far as Jammu is concerned, what is the information? There is tension building up between the migrants and the local people. Some say that the migrants are more in number than the local population in the city of Jammu. This is the information I have; I am not sure of it. But the migrants have come in thousands and thousands under compelling circumstances, because it was not possible for them to stay there. But the Government could not provide them the relief they needed. They cannot get a house to stay. They cannot get food. They are on the streets. They are crowding the lanes and the bylanes of the city. And this is creating problems for the local people. The migrants are unable to get their children and wards admitted into the schools and colleges. Therefore, they are forced to come to Delhi; they are going to Bombay, to Calcutta, to Madras or wherever they hope to get admission for their children. The Government has not made any arrangements for them. One Member said that some provision should be made for the admission of the migrants' children into the schools and colleges in different parts of the country. But the Government has not taken any steps. Successive Governments have failed to do anything. It is incumbent on the Government to do something tangible for the migrants and see that no tension is

[Shri Sukomal Sen]

allowed to build up, between the migrants and the local people. If tension is allowed to build up, it will be another calamity outside the Valley. So a comprehensive effort should be made to solve this problem. The Government should take a political look at the problem with a broader perspective in tackling this problem, *(time-bell rings).* The earlier Prime Minister, Mr. Chandra Shekhar, gave a certificate that the Pakistan is showing good signs of positive response. All of us-have now known and experienced what sort of positive response they are showing. As days pass by, under Pakistani instigation more and more men are being killed, more and more people are being kidnapped. So this Government should take effective measures. At least this Government is not going to collapse today or tomorrow. We have not voted against you yesterday. So this Government is getting some time, some respite. So long as you are in Government. please do something tangible for bringing about **a** political solution to the problem of Jammu and Kashmir so that the people are not alienated, so that good sense prevails over the people there, so that they are brought into the mainstream of the country and peace is restored and a popular Govern-is brought into power in the State. With these words I conclude.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominated); Sir, on a point of order or rather a point of clarification. There is circulated a Statement of Objects and Reasons. I will just read it.

"For the general election for the Tenth Lok Sabha, the Election Commission had recommended that the Presidential notification under Section 14(2) of the Representation of the People Act

If you see Section 14(2), it states the purpose:

The President shall, by notification published in the **Gazette of India on** such date as may be recommended by the Election Commission, **call upon all** parliamentary **constituencies to elect** Members in accordance with **the** provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder'

This is a substitution for the existing Section 73 A and the other Section. Now, may I know from the Minister from where he derives his power to postpone elections either through the Constitution or through the Representation of the People Act?

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not think it is a point of order. It seems that the hon. Member was not in the House when I had piloted the Bill. I had very categorically stated that the Election Commission had recommended that the elections to the parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir should not be held together with the other parliamentary constituencies in the country and had specifically recommended that under Section 14(2) the notification be limited to all the other parliamentary constituencies except those of Jammu and Kashmir, and it is this that necessitated that Section 73 be ammended so that the notification under 14(2) could be issued. If you read the statement of Objects and Reasons also, it would clarify.

श्री कृष्णलाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1991, यद्यपि यह इस समय सदन की एक मजबूरी बन गया है कि वह इसको पास करे, मैं इसका विरोध करना चाहूंगा । मैं इसका समर्थन करने के लिये अपने आपको समझा नहीं पा रहा हूं । उसके तीन कारण हैं--एक तो यह है कि इलैक्शन कमीशन ने दोहरे मापदंड अपनाये । इलैक्शन कमीशन ने पिछली बार सैक्शन 73ए में संशोधन द्वारा आसाम और पंजाब को एक्सक्लूड करने के अधिकार लिये । जिनको एक्सक्लूड करने का अधिकार दिया था उसके तो चुनाव कराने की घोषणा की गयी और जिनको एक्सक्लूड करने का अधिकार नहीं था जिस दिन राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी हुई 19 को उससे एक दिन पहले आसाम को एक्सक्लूड करने का अधिकार लेने के लिये

राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की । वैसे तो इससे मुझे एक थोड़ी आशा बंधी कि शायद हमारे इलैक्शन कमीशन का और सरकार का काम करने का ढंग ऐसा है कि वह अगर जम्मू कश्मीर का एक्सक्लूड करने का अधिकार ले रहे हैं तो अब इसके चुनाव जल्दी हो जायेंगे । पहले उन्होंने जो पंजाब और आसाम को एक्सक्लूड करने का अधिकार लिया तो उसके चुनाव करवाये, तो शायद अब जम्मू-कश्मीर के चुनाव जल्दी हो जायें । लेकिन यह दोहरे मापदंड क्यों ? एक और भी कारण है । पंजाब में लोक सभा की 13 सीटें हैं, आसाम में 14 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं । इन 6 सीटों में दो जम्मू कश्मीर की, एक लद्दाख क्षेत्र की और कश्मीर वैली की 3 सीटें हैं । वहां अगर कोई आतंकवादी है या डिस्टरबेंस है या वायलेंस है या हिंसा है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें चुनाव नहीं हो सकते तो केवल तीन सीटें हैं । एक मिनट के लिये मान लिया जाये दलील के लिये कि वह तीन सीटें संकट में हैं तो दूसरी ओर बाकी जो रीजन हैं-- लद्दाख वाले चुनाव चाहते हैं, जम्मू वाले चुनाव चाहते हैं और तीनों सीटों में वह चुनाव कराने के पक्ष में हैं और वहां कोई गड़बड़ नहीं है । जहां आसाम में 14 सीटों पर गड़बड़ थी और पंजाब की 13 सीटों पर गड़बड़ थी, वहां पर तो सिक्योरिटी के पूरे एरेंजमेंट करने के वायदे और दावे करके चुनाव कराने के लिये तैयार हो गए और जम्मू कश्मीर को हमने एक्सक्लूड कर दिया । मैं समझता हूं कि यह पक्षपातपूर्ण निर्णय है और ऐसा निर्णय सरकार को भी नहीं मानना चाहिये था और इलैक्शन कमीशन को भी ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिये था जिससे कि इस तरह के अर्थ निकाले जायें कि पंजाब के बारे में उनका एक मापदंड है, आसाम के बारे में दूसरा और जम्मू कश्मीर के बारे में तीसरा मापदंड है । मैं समझता हूं कि हमने संकल्प किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही यह समस्यायें हल की जायें तो अब तीनों प्रदेशों में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है डैमोक्रेटिक बेसिस है उसको ही अपनाना चाहिये और इसके द्वारा ही समस्याओं का हल करने के लिये हमें एक रास्ता, एक राह अपनानी चाहिये यह मैं चाहता हूं ।

एक बात और भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात का अभी तक फैसला नहीं हो पाया, चाहे सरकार जवाब दे या कोई तो जवाब दे कि यह लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन खराब है इसका निर्णय कौन करता है ? राष्ट्रपति करता है प्राइम मिनिस्टर करता है, केबिनेट करती है या वहां की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करती है या इलैक्शन कमीशन स्वयं करता है ? अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि इलैक्शन कमीशन ने अगर लॉ एंड आर्डर के बेसिस पर जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड किया है तो यह रिपोर्ट किस की है? क्या गवर्नर की है या केबिनेट की है? या और किसी की है? यह किसकी रिपोर्ट है ? महोदय, मेरे सामने पंजाब का उदाहरण है। पंजाब में इलेक्शन पोस्टपोन किए गए तो गवर्नर ने रिजाइन कर दिया कि मेरे से पूछे बिना इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए । मैं पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को जानने का सोर्स क्या है ? क्या वह सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है ? क्या जम्मू कश्मीर के बारे में स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि सारा

[श्री कृष्णलाल शर्मा]

प्रदेश हिंसा से लिप्त है इसलिए वहां चुनाव नहीं हो सकते?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हम जम्मू कश्मीर की गलत तस्वीर दुनिया में पेश कर रहे हैं। हम दुनियाको यह बताना चाहते हैं कि सारे जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़क रही है और कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां चुनाव हो सकें। यह तो गलत तस्वीर पेश की जा रही है। जम्मू में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लद्दाख में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम दुनिया में अपनी तस्वीर क्यों बिगाड़ रहे हैं? अगर किसी लिमिटेड एरिया में ऐसी चीज है तो उसे उचित ढंग से पेश किया जाए न कि सारी दुनिया में हम यह कहें कि हम चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं हैं। क्या मिलिट्री के द्वारा भी हम सिचुऐशन को कंट्रोल नहीं कर सकते? मैं समझता हूं कि यह ऐसी बात है कि जिसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बात को इसलिए भी बलपूर्वक कह रहा हूं कि आगे भी जो निर्णय हो रहे हैं वे इस रूप में हो रहे हैं कि हम अपने राजनीतिक स्वार्थो से प्रेरित होकर निर्णय ले रहे हैं। हम प्रशासनिक कारणों से या लोगों के हित को ध्यान में रखकर या लॉ एंड आर्डर की सिचुऐशन को सामने रखकर निर्णय नहीं ले रहे हैं और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाएंगे तो आज एक निर्णय होगा, कल दूसरा होगा और ये निर्णय उस प्रदेश की स्थिति को और बिगाड़ देंगे।

अभी भंडारे साहब बोल रहे थे और अहलुवालिया जी ने भी कहा कि जो राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगाया गया उसकी वजह से स्थिति बिगड़ गई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति शासन इससे पहले कभी लागू नहीं हुआ? क्या वहां गुलाम शाह को हटाकर फारूक को लाने के लिए कोशिश नहीं हुई? क्या यह खेल पहले नहीं खेला जाता रहा? इसलिए महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम, ये ऐसी सेंसिटिव स्टेट्स हैं कि इनकी जो सिचुऐशन है That has gone beyond partisan politics.

अगर इन स्टेट्स के बारे में हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के साथ कोई निर्णय लेने की बात करेंगे तो वह गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में निश्चित रूप से सारी परिस्थितियों को ध्यान रखकर बात की जाए।

अभी जो मैंने वक्तव्य पढ़ा, उसमें कहा गया है कि मेजर पोलिटिकल पार्टीज से सलाह की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी पार्टियां हैं? उनके नाम बताए जाएं। मैं यह कह सकता हूं कि कम से कम हमारी पार्टी से तो सलाह नहीं ली गई थी। अभी जो पंजाब के इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं वे किस आधार पर पोस्टपोन हुए हैं?

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: Many candidates **have** been killed.

श्री कृष्णलाल शर्मा : वहां पर जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं उनसे सलाह नहीं ली गई बल्कि दूसरी पार्टियों के कहने पर इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए। क्या सलाह करने का यह तरीका है? मान लिया कि इतने लोग मरे। जिनके कैंडीडेट मरे, उन पार्टियों ने चुनाव पोस्टपोन करने की मांग नहीं की, जो पार्टी चुनाव लड़ रही थी उसने चुनाव पोस्टपोन करने के लिए नहीं कहा लेकिन जो पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही थीं, उसके दबाव में आकर चुनाव पोस्टपोन कर दिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन सी मेजर पोलिटिकल पार्टीज हैं जिनके इशारे पर यह निर्णय लिया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब तक हम जम्मू-कश्मीर के बारे में अपनी नीति को ठीक नहीं करेंगे तब तक यह कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी। हमारी पार्टी काफी समय से इस बात को कहती

आ रही है कि धारा 370 अपनी सार्थकता खो चुकी है, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है और कश्मीर के हालात ने इस बात को साबित कर दिया है। मैं यह कह सकता हूं कि सारे देश में, सारे भारत में कश्मीर घाटी एक ऐसा एरिया है जिसको मैं आज नॉन-सैक्युलर एरिया कह सकता हूं और वह एरिया उस जगह पर है जहां हमने धारा 370 का प्रोटेक्शन दे रखा है। धारा 370 इसलिए लगाई गई थी कि हम कश्मीर को मेन-स्ट्रीम में लाएंगे, हम सब लोगों को भारत के साथ एक सूत्र में पिरोएंगे लेकिन आज क्या स्थिति पैदा हो गई है। आज जम्मू नाराज है, लद्दाख नाराज है? लेकिन जिनको हम खुश करने की कोशिश सारी उम्र करते रहे, वे हमारे काबू में नहीं हैं, वे हमारे बस के बाहर हैं। पाकिस्तान अपना खेल खेल रहा है। हम पाकिस्तान के बारे में कोई कड़ी नीति नहीं अपनाते। हम स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा ऐक्शन है जो सरकार ने उठाया हो। पाकिस्तान क्लियर-कट ऐक्शन ले रहा है। वह हमारे अंदर इंटरफियर कर रहा है। वह इनफिल्ट्रेटर्स भेज रहा है, आर्म्स भेज रहा है, लेकिन हमारी सरकार बताये कि उस ने कौन-सा ऐसा ऐक्शन लिया है जिसे हम उनके ऐक्शन को काउंटर कर सकें ताकि पाकिस्तान रियलाइज़ कर सके कि वह हमारे यहां इंटरफियर न करे।

श्रीमन, मैं जब नॉन-सेक्यूलर एरिया की बात करता हूं तो मैं एक बड़ी गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास संविधान है। संविधान में 1976 में हमने संशोधन किया, उसके प्रियंबल में हमने थोड़े शब्द चेन्ज करके ये शब्द जोड़े–
"Now, having solemnly resolved to cons titute India into a Sovereign, Socialist, Secular. Democratic Republic . ये शब्द हमने प्रियंबल में जोड़े हैं। लेकिन आर्टिकल 370 के कारण हमने जम्मू-काश्मीर के बारे में यह लिखा हुआ है कि– "Omit the words 'Secular, Socialist'. क्या हम जम्मू-कश्मीर में सोशलिस्ट और सेक्यूलर शब्द प्रियंबल के वहां पर एप्लाई नहीं कर सकते? हमने यह कहा– "Assuring dignity of the individual and the unity and integrity of the nation" तो हमने जम्मू-काश्मीर के लिए कहा कि– "Omit the word 'integrity". हम सारी दुनिया में यह घोषणा करते फिरते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में हम "इंटिग्रिटी" शब्द को एप्लाई नहीं कर सकते। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से हमने जो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स ऐक्ट में सेक्शन 29ए का जो संशोधन किया, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन आफ पोलिटिकल पार्टीज में यह कहा कि सब पार्टीज अपने संविधान के सोशलिस्ट सेक्यूलर एवं अन्य कुछ आवश्यकताएं शामिल करें जिनके आधार पर पोलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान किया गया है और यह कहा है कि जो पोलिटिकल पार्टीज रजिस्टर होंगी, वही चुनाव लड़ सकेंगी। आपका यह आर्टिकल 29ए जम्मू कश्मीर पर ऐप्लिकेबल नहीं है। रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स ऐक्ट की धारा 29ए जम्मू कश्मीर पर ऐप्लिकेबल क्यों नहीं है? अगर हमारी यह नीति है कि हम अपनी सैक्यूलर नीति की दुनिया भर में घोषणा करते रहेंगे लेकिन हम जम्मू कश्मीर पर उसको लागू नहीं करेंगे तो हम दुनिया को यह नहीं बता सकते कि जम्मू कश्मीर हमारा इंटिग्रल पार्ट है। इसलिए मैंने इस बात को बल-पूर्वक कहा है कि धारा 370 को हटाकर इस स्टेट को ऐट पार विद अदर स्टेट्स लाएं और सभी कानून जो देश में बनें, उनको जम्मू कश्मीर पर भी लागू करें। (समय की घंटी)

श्रीमन, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे खेद है कि जम्मू-कश्मीर वैली से दो लाख से ऊपर लोग इस समय वहां से निकाले जा चुके हैं। वे लोग जम्मू में हैं, देश के अन्य भागों में हैं, दिल्ली में हैं। लेकिन न तो केन्द्र सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान दे रही है, न प्रदेश सरकार उनकी तरफ

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

ध्यान दे रही है। मुझे लगता है कि उनको लावारिस मान लिया गया है। अगर वहां से उनको निकाला गया है तो इसमें उनको दोष नहीं है। सरकार की कमजोर नीतियों के कारण ही उनको अपने घरबार छोड़कर वहां से आना पड़ा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां के जो लोग अनइंप्लाइड हैं उनको नौकरियां दी जाएं, उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए। उनके खाने के लिए, रहने के लिए इंतजाम होना चाहिए। जो रिफ्यूजी हैं उनको बसाना हमारी मारेल रिस्पांसिबिलिटी है, उनको वापस भेजना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक उनको वापस नहीं भेजते तब तक यह सरकार उनकी पूरी तरह से जिम्मेवारी निभाएं। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इस समय तक कितने रिफ्यूजी काश्मीर वैली से हमारे पास आ चुके हैं और उनके लिए क्या क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं।

हम जम्मू-काश्मीर के बारे में जब तक कोई फर्म और कंसिस्टेंट पालिसी नहीं अपनाएंगे तब तक कितनी बार आप चुनाव पोस्टपोन करते जाएं लेकिन जम्मू-काश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिए कम से कम जम्मू और लद्दाख को बलि पर न चढ़ाया जाए। जम्मू में लोकल बाडीज़ के चुनाव हो सकते हैं, गवर्नर रूल में कोई भी चुनाव वहां नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि लद्दाख की मांगें भी पूरी की जाएं और जम्मू की भी पूरी की जाएं। ऐसा न हो कि जम्मू और लद्दाख को लगे कि हम जब तक उठेंगे नहीं यह सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। वे टैरेरिज़्म के मार्ग पर न आयें, इसके लिए जरूरी है कि हम समय पर जम्मू रीजन और लद्दाख रीजन की भावनाओं का आदर करें और उनका सम्मान करें। इन शब्दों के साथ मैं यह समझता हूं कि जो यह पक्षपातपूर्ण और दोहरे मापदण्ड पर आधारित जो विधेयक लाया गया है, वह ठीक नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन निश्चित रूप से मैं यह चाहता हूं कि चुनाव आयोग को जो इस संशोधन के जरिये जो जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का अधिकार दे रहे हैं, चुनाव कराने की जो तारीख तय करे तो उनको उसकी कोई एक सीमा बांधनी चाहिए।

कश्मीर के लिए कहा गया है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। आज कश्मीर की हालत यह है कि वहां से जो 6 लोक सभा की सीटें हैं, चुनाव न होने के कारण लोक सभा में वह सीटें खाली पड़ी हैं। वहां का कोई प्रतिनिधि इस देश की लोक सभा में नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You are giving an amendment. At that time also, you will be able to speak.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I know about that; **Sir.**

मैं यह कह रहा था कि जो 6 लोक सभा की सीटें कश्मीर से हैं उनका कोई प्रतिनिधि इस देश की लोक सभा में नहीं है क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं कराये जा सके। इसी प्रकार से वहां की जो विधान सभा है वह भी आज जीवित नहीं है। कश्मीर का एक भी प्रतिनिधि आज के केन्द्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। आज हालत यह है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं गुलाम रसूल मट्टू जो नेशनल कांफ्रेंस के सदस्य हैं आतंकवादियों के कारण अपनी जान खतरे में होने के कारण उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे रखा है। उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन आतंक-

वादियों के डर के कारण वह इस सदन की बैठकों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस बात को साल, सवा साल हो गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह संशोधन है इसमें इस बात की चर्चा की गई है और इसके उद्देश्यों और कारणों में यह लिखा हुआ है:

> "जम्मू-कश्मीर की दशा में, निर्वाचन आयोग ने यह महसूस किया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी और उस राज्य में निर्वाचन के लिए मतदान का समय सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा घोषित किया जायेगा।"

इस पर मैं बाद में आऊंगा।

लेकिन जब यह चुनाव वहां टाले गये तो उसका कारण यह बतलाया गया कि वहां पर निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयरहित चुनाव कराना संभव नहीं है। आखिर यह कब तक संभव हो पायेगा? आज की जो केन्द्रीय सरकार है इसको ही कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जम्मू-कश्मीर को हमारे राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उससे जोड़े रखना है। जम्मू-कश्मीर के लोगों को महसूस नहीं होना चाहिए कि वे उपेक्षित लोग हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ऐसी हालत कायम करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया पुनः बहाल हो सके इसके लिए सरकार को जितने भी सम्भव उपाय है, जितने भी संभव कदम हैं उनको उठाने चाहिएं।

इस संबंध में दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में जिस तरीके से चुनाव टाले गये वह इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस पर एक बहुत बड़ा कलंक है। 22 तारीख को वहां पर चुनाव होना था। 20 तारीख को चुनाव आयोग ने सारे देश को बतलाया कि 22 तारीख को पंजाब में चुनाव होगा लेकिन जो तारीख चुनाव के लिए मुकर्रर थी ठीक उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा कि पंजाब में निष्पक्ष और स्वतंत्र हालत में चुनाव कराना संभव नहीं है इसलिए वहां का चुनाव तीन महीने के लिए टाला जा रहा है। आज की जो सत्ताधारी पार्टी है उसने वहां पर जो नामांकन हुए थे उनमें अपने किसी उम्मीदवार का नामांकन दाखिल नहीं किया था क्योंकि इनके नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे उन्होंने पंजाब में चुनावों के बहिष्कार का एलान कर रखा था। इस कारण कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी व्यक्ति ने न तो लोक सभा के लिए और न ही विधान सभा के लिए नामांकन दाखिल किया। अब स्थिति यह है कि चुनाव आयोग ने यह कह रखा है कि 22 से 25 सितम्बर को वहां चुनाव होंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं आई है, लेकिन लगता है कि जो सारी चुनावों की प्रक्रिया है उसको निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसलिए मेरा यह कहना है कि पंजाब में जैसा कि लेफ्टि० जनरल अरोड़ा ने सदन में यह मांग उठाई है कि पंजाब में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को कायम करने के लिए, उनको बहाल करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पुनः स्थापित करने के लिए ठीक से सरकार की ओर से कदम उठाये जाने चाहिये। इन शब्दों के साथ यह जो संशोधन विधेयक है, इसका मैं समर्थन करता हूं और हमारा जो संशोधन है उस पर बाद में बोलूंगा।

SHRI A. G. KULKARNI; Mr. Vice-Chairman, I am thankful to you for giving me five minutes to speak. Usually, I don't speak on such subjects. My concern is, the situation in Punjab is deteriorating day by day and during the last 18 months or, say, about 2 years, no policy decision, which will inspire confidence in the people, has been taken by any Government. It was really to the credit ot Chandra Shekhar Government which announced elections because we political **par**

[Shri A. G. Kulkarni]

ties in this House always speak of starting a political dialogue. I think, Sir, this problem could be solved through political dialogue and through debate and discussion with the people of the concerned State. Mr. Vice-Chairman, Pakistan is playing a proxy war. It is actually a war which is going on in Kashmir and in Punjab also. They are supplying all types of arms and infiltrating terrorists. So the Government has to take very positive and strong steps; otherwise, by amending and issuing Ordinances this problem is not going to be solved. I am very much concerned again, as my frietnds here are about the release of Mr. Doraiswamy. I read in the papers and I see that the morale of the officers of the Indian Oil Corporation has gone down to such an extent that it does not give any credit to the Government. The officers are abducted in some cases. Some are released and some are killed. This type of knee-jerk reaction is really reprehensible. Mr. Minister, I want that this Doraiswamy episode should be dealt with as early as possible. It is not only an agony of Mrs. Doraiswamy but it is the agony of entire official cadre whether of Indian Oil Corporation, Doordarshan or any other organisation. It does not give any credit to the Government. In the last 18 months all the Governments have failed. At least our Government should find a solution for this. Then, Mr. Vice-Chairman, I would like to make my last point. At the outset, I want to say that the behaviour of the Election Commission during the last election was totally reprehensible. I have addressed one letter myself to the President of India criticising the decisions of the Election Commission of postponing, advancing, countermanding and stopping the results of the elections. It smacks of political intervention in the working of the Election Commission. Sir, the public discussion and debate between the then Prime Minister, Shri Chandra Shekhar and the Chief Election Commissioner about the postponment of the elections shows the worst kind of attitude of the Election Commissioner. We had an illustrious galaxy of Election Commissioners. But the present incumbent had brought the entire Election Commission to a low level. Mr. Vice-Chairman, my friend, Shri Sharma, just now made reference to Section 29(A) regarding the recognition of political parties. The procedure of recognising a political party is mentioned in that Section.

Sir, I draw the attention of my young, intelligent and bouncing Law Minister and Parliamentary Affairs Minister to question No. 462 dated 28th February, 1991 which I put in this House. I wanted to know whether the Election Commission had received the representations regarding ban on communal parties for submission of false affidavits etc. Sir, I quote the Law Minister's reply to this question which says that as per the Commission none of this was based on the ground **that** false affidavits had been submitted by the political parties for securing recognition. So, what Shri Sharma was mentioning was this issue. This is a total untruth. I challenge the Election Commission. There is another news item dated 5th April, 1991 in the *Indian Express* stating, "Are the affidavits genuine? Dr. Swamy". I have mentioned here what the *Indian Express* has stated it had been mentioned that the affidavits were filed which were contested by the Janata Dal representatives. On this, the late Mr. Peri Shastri ordered an inquiry. The officers went to Ahmedabad. Then the officers sent **a** report that some of the affidavits, totalling 32 or. so. the totally false, and these are submitted by the then President of **the** Janata Dal, Mr. Indubhai Patel and his Secretary, Shri Subramaniam Swamy, I would seek an assurance from my young friend. We are, here, fighting **a battle** against corruption. My dear frined, please inform this House whether these affidavits are lying there or whether the inquiry has been scuttled because during the interim period of the previous Government, Ms. Rama Devi was not made the Chief Election Commissioner. Why? Because, she was upright and honest.

Perhaps, the Ministry or somebody might have thought that the present incumbent might be useful. Why? To scuttle such an enqiury. I request you. Mr. Minis-

ter, for the sake of equity, for the sake of justice. Please inform this House whether such an enquiry was ordered by the **late** Peri Shastri, where the affidavits were found false and, if so, what action the Government is going to take against the Election Commission? Thank you.

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का बहुत हिचकिचाहट के साथ और दुख के साथ समर्थन करता हूं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में दिनोंदिन ऐसा एरिया जो है वह बढ़ता चला जा रहा है जहां हम चुनाव नहीं करा पाते हैं, जहां हम जनवादी प्रक्रिया को रख नहीं पाते हैं। यह अत्यंत ही दुखद बात है। अगर ऐसे ही होता गया तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे संविधान का क्या होगा और हमारे गणतंत्र का क्या होगा। अभी एक बात हमारे मित्र शर्मा जी ने कही कि कश्मीर घाटी के लोग नान-सेकुलर हैं। तो मैं सोचने लगा कि क्या यह बात सच है। जब हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हो गये, हमारे देश के जितने भी इलाके ऐसे थे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वह पाकिस्तान में चले गये तो कश्मीर घाटी ही ऐसी थी जिसने जिन्ना साहेब के साथ जाने से इन्कार किया। शायद शर्मा जी को यह भी मालूम होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू गद्दी पर बैठे ही थे तो थोड़े ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। उस वक्त हमारी फौज नहीं पहुंच पाई थी, एक हफ्ते से ज्यादा देर लग गई। उस वक्त कश्मीर के मुसलमानों ने रोड्ज को काट दिया था, पानी काट दिया था और पाकिस्तानी फौज को रोक दिया था। उस दिन तो वह सेकुलर थ और आज शर्मा जी यह समझते हैं कि वह सेकुलर नहीं हैं। हम लोगों को इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये। अगर शर्मा जी के दृष्टिकोण से और हिन्दू मुसलमान के दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो यह बिलकुल घातक होगा। ऐसा मत कीजिये। ऐसा कर के इस देश को हम और आप बरबाद कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी तह में हम लोगों को जाना चाहिए कि आज कश्मीरी क्यों बगावत में हैं। दूसरी बात जो उन्होंने उठाई उससे मैं कुछ सहमत सा हूं कि इस या ऐसे सवालों पर हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। कश्मीर का सवाल है, पंजाब का सवाल है, इन सवालों पर कम से कम राष्ट्रीय दष्टिकोण से विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं जो आसाम का सवाल है वह दूसरी केटेगरी का है। वहां पर धार्मिक कट्टरवादिता नहीं है, वह लोग रिलीजियस आधार पर देश के टुकड़े नहीं करना चाहते हैं, वह राजनीतिक कारणों से चाहते हैं इसलिए इन दोनों को हमें मिलाना नहीं चाहिये। हम सब लोग मिल कर के काम करें तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सब मिलें तब तो। शर्मा जी का ख्याल है कि कश्मीर नॉन-सेकुलर हैं। शर्मा जी का ख्याल है कि उनको जो आर्टिकल 370 मिला हुआ है उसको तुरंत रद्द कर दिया जाए। आर्टिकल 370 एक नेशनल कमिटमेंट है। जब कश्मीर के लोग भारत के साथ आ रहे थे तो हमने आर्टिकल 370 का वादा निभाया (व्यवधान) यह कहीं नहीं लिखा है कि यह कितने दिनों के लिए टेम्पोरेरी है (व्यवधान) टेम्पोरेरी तो हरिजनों के लिए आरक्षण भी था, टेम्पोरेरी तो यह भी था कि हम 10 वर्ष के अन्दर सब को साक्षर बना देंगे। बाकी बात करते ही नहीं हैं इस पर आ जाते हैं कि यह टेम्पोरेरी था। बाकी बातों को कीजिये समग्र रूप से चीजों को देखिये (व्यवधान) नहीं, नहीं कालबद्ध टेम्पोरेरी नहीं है। . . (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : अनुच्छेद है, वह देखिये, उस में टेम्पोरेरी लिखा है। *(Interruptions)*

SHRI A. G. KULKARNI: How **can** you say that the reservations are temporary? How do you say that? It is a **national** commitment

श्री चतुरानन मिश्र : यह टेम्पोरेरी तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप बाबरी मस्जिद को उठाते रहें तो यह परमानेंट हो जाएगा, इस शताब्दी में क्या

[श्री चतुरानन मिश्र]

अगली शताब्दी में भी चलता रहेगा। (व्यवधान) आप चलने दीजिए तब तो। हम तो इसको हल कर सकते हैं लेकिन आप मदद भी तो कीजिए। हिंदू राष्ट्र, हिन्द राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं। कौन रहेगा हमारे साथ। आपके चलते भारी झंझट हो रहा है, दूसरे भी भड़क रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने पाकिस्तान बनवाया.. (व्यवधान) कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। आज इसका समर्थन कर रहे हैं।

SHRI A. G. KULKARNI: Mathur Saheb, your party in Maharashtra produced a book wherein it *is* alleged that late Lokmanya Tilak was not secular. This is the character of your party.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: No, we withdrew it the next day. It was withdrawn.

SHRI A. G. KULKARNI: The B.J.P. published a book wherein this was stated and when the people of Maharashtra started agitation, they thought that they would lose election, which they have already lost, and so this allegation was withdrawn.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I want to inform that he is misleading the House. *(Interruptions).*

THE VICE CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) Mr. Kulkarni asked Shri Chaturanan Mishra whether he would yield and Shri Mishra yielded.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: But he is misleading the House. My **party** did not come out with the book. The day it was noticed, it was withdrawn the next day.

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : लिख तो सच है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कुछ सच नहीं लिखा है।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : आपका हृदय है। नाथू राम गोडसे है... (व्यवधान)

You don't respect Tilak also. That is your character.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: The Congress has its own name. You d»-owned Patel, you disowned Tilak. **YOB** have disowned, not we.

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभापति महोदय, अभी की बहस से फिर एक बात तय हो गयी कि भाजपा के साथ जाकर संयुक्त रूप से काश्मीर में काम नहीं किया जा सकता क्योंकि सदन में जब ये दोनों इस तरह से करते हैं तो काश्मीर जाकर और झंझट हो जाएगा। इसलिए ये लोग उस यूनाइटेड मूव में रखने लायक आदमी नहीं हैं। यह स्पष्ट है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एक बार बंटवारा आपने करा दिया अब दूसरा और कराएंगे ?

श्री चतुरानन मिश्र : ... (व्यवधान) इनका कैसा दृष्टिकोण है। मिजोरम का जो समझौता हुआ उसमें लिखा हुआ है कि बगल के जो दूसरे देश हैं उनके साथ वे व्यापार कर सकते हैं। ये काहे नहीं बोलते हैं कि यह डिस्क्रिमिनेट्री है ? चूंकि कश्मीरी मुसलमान हैं, इसलिए ये बोलते हैं, और कोई कारण नहीं है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मिजोरम का विरोध किया था... (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : इसका अभी विरोध नहीं किया है... (व्यवधान) सुन लीजिए। ये लोग, पूंजीपति लोग काश्मीर में जमीन खरीदने के लिए एकदम ललचा रहे हैं और इसीलिए कहते हैं अनुच्छेद 370 खत्म कर सेठों को कश्मीर में घुसने दीजिए। काश्मीर में क्या हुआ था

शेख अब्दुला के टाइम में विदाउट कम्पेन-सेशन दिये जमींदारी प्रथा खत्म की गयी थी, जैसा सारे देश में कहीं नहीं हुआ था। बाहरी लोगों को कमजोर वर्ग के या विशेष क्षेत्रों में जमीन खरीदने पर पाबन्दी है।

(व्यवधान)

मैं आपसे कह रहा था कि हर जगह ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ट्राइबल एरियाज में जमीन खरीदने के लिए. . . (समय की घंटी) बहुत से दूसरे लोगों ने टाइम ले लिया है इसलिए हमारे टाइम में उसको मत एडजस्ट कीजिए। जो दूसरे बोले हैं उसको काट दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please be brief, make your point.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am always to the point. Tell me when I have gone astray. मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा था, जमीन वगैरह के बारे में कि सर्टेन प्रोटेक्शन देना जरूरी है। काश्मीर के लोगों को अगर हम साथ रखना चाहते हैं तो जो नेशनल कमिटमेंट है उसको अभी हम रखेंगे। अगर ऐसी हालत पैदा हो जाएगी तो ठीक है हम सब लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी ऐसी हालत पैदा नहीं हुई है। मैं कह रहा था कि कश्मीरी क्यों बदल गये हैं? इसमें कहना हमारा है कि वहां कुछ ऐसे भेदभाव किये गये। वहां उचित चुनाव नहीं होता था। कांग्रेस के लोग तो बिगड़ जाएंगे क्योंकि उन्हीं की सल्तनत के टाइम में सही ढंग से चुनाव नहीं हुए। जब चुनाव नहीं होने दीजिएगा तो लोग हथियार उठाएंगे, बगावत करेंगे। अब उन्होंने रिलीजन और पोलिटिक्स को मिक्स कर दिया है। यह सबसे बड़ा झंझट वहां हो गया है। यह झंझट तो

5.00 P.M. हमारे शर्मा जी भी करते हैं रिलीजन और पालिटिक्स को मिला करके, बाकी भारत में करते हैं। लेकिन वही काम उन लोगों ने भी किया। माननीय सदस्य भंडारे साहब ने प्रेस कौंसिल की रिपोर्ट दी। सच्ची बातें कुछ उन्होंने कही हैं। लेकिन, सही बात क्या है कि हम जो सच्ची से सच्ची बात कहेंगे, उसको काश्मीर के लोग नहीं मानते और झूठ से झूठ बात अगर वह मिलिटेंट लोग बोल देते हैं, तो उसी रयूमर को वह सच समझते हैं कि आर्मी ने यह किया, वह किया, या कोई भी चीज की।

इस देश का यही एक वातावरण हो गया है कि हमारी सच्ची बात को मानने के लिए वह तैयार नहीं होते हैं। पंजाब में भी यही बात हो रही है कि हमारी सच्ची बात को वे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस वातावरण को समाप्त करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम एक उदाहरण देते हैं--आज की बात नहीं है (समय की घंटी)--हमें (व्यवधान) पहले भी ऐसा होता था। अब भुट्टो साहब की हत्या या फांसी हुई और बस जली कहां--श्रीनगर का। माना भाई, भुट्टो साहब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधान मंत्री थे, इसलिए उनके दुख में कश्मीरियों ने बसें जलायीं। जब भुट्टो साहब की हत्या करने वाले प्रेज़ीडेंट जिया उल हक पाक हवाई जहाज से गिर कर पाकिस्तान में ही मर गये तब भी हमारी बसें जलाई गईं। यह हास्यास्पद है। कुछ भी हो, तब भी हमारी बस जलेगी। . . . . (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जमीन खरीदने का अधिकार छीन लिया किसी ने. . . . (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : जमीन तो आप खरीदना चाहते ही थे। यह तो हम जान रहे हैं आपकी बात, लेकिन हम उसके होने देने के पक्ष में नहीं हैं।

मैं यह कह रहा था कि आर्मी जहां जाएगी, हमको अपनी आर्मी पर भरोसा है, हम उसकी बहुत इज्जत और कद्र करते हैं, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि हम कहीं आर्मी भेजते हैं, तो उसे

[श्री चतुरानन मिश्र]

भजन कीर्तन के लिए नहीं भेजते हैं। वह रिप्रेसिव मेजर्ज लेगी। अगर हम पैरा मिलिट्री को भेजेंगे, तो वह रिप्रेसिव मेजर्ज लेगी।

इसीलिए अच्छा तरीका है कि वह हटा लें। अगर भजन भाव के लिए भेजना है, तब तो शर्मा जी से कुछ साधु लोगों को ले लेना चाहिए था। उनको भेज देना चाहिए था, वह भजन भाव करते। पुलिस फौज से जोर जुल्म होगा ही।

मैं आपसे एक दो बातें सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि जो लोग सरंडर कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए अलग-अलग से इंतजाम कर दिया जाए ये लोग पाकिस्तान के ट्रेंड किए हुए हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में वहां के लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ होने लगे हैं। कुछ दिन पहले तो नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने प्रासस शुरु किया है।

इसीलिए जो सरंडर करते हैं, उनको भी अगर आप जेल में रखते हैं, तो वह कहते हैं कि सरेंडर करके हमको क्या फायदा हुआ।

असल में इस डिबेट में तो होम मिनिस्टर को यहां रहना चाहिए था। हम लोगों को कौन जवाब देगा, ला मिनिस्टर इसका जवाब दे नहीं सकते।

अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि कश्मीर की जो सीमा है, उपसभाध्यक्ष जी,... (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटि है।

श्री चतुरानन मिश्र: वह कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी अलग चीज है, लेकिन बार्डर सील नहीं कर सकता है ला मिनिस्टर। और बार्डर वहां सील होगा नहीं, क्योंकि ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि पूरी सीमा सील नहीं की जा सकती है। हमको इस रियलिटी को मानना पड़ेगा कि ऐसी बात है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि जो जेल में बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, उनको फ्री कर दिया जाए। उनके ऊपर चार्ज नहीं है, तो उनके साथ मान बता का एक संबंध कायम कीजिए। पोलिटिकल निगोसिएशन जो शुरू हुआ था, रह रह कर वह फिर खत्म हो जाता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि उसके बारे में आप प्रासेस को शुरू करें, ताकि हम लोग जनवादी व्यवस्था ला सकें। तुरंत तो हम इस स्थिति में नहीं हैं कि वहां पर इसे कर सकें।

कई अन्य माननीय सदस्यों ने रेफ्यूजीज के बारे में—जो लोग वैली से भाग करके यहां आये हैं या भगा दिये गये हैं, उन लोगों की व्यवस्था के बारे में कहा। उसमें मुसलमान भी हैं उनके लिए हम लोगों को अविलम्ब सोचना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में न तो पंजाब की समस्या का समाधान होगा और न ही कश्मीर की समस्या का समाधान होगा। इसमें टाईम लगेगा। शायद असम में भी कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहता हूं। इन सब सवालों को हल करने में टाईम लगेगा इसीलिए हमको शरणार्थियों के साथ ऐसा करना चाहिए ताकि वे उचित जीवन बिता सकें।

जो लद्दाख क्षेत्र की समस्या है, उसकी चर्चा इन्होंने की। उस पर भी गंभीरता से, खाली चुनाव के लिए नहीं, उनकी अन्य समस्याओं को देखने के लिए विचार करना चाहिए।

मैं अंतिम बात करके समाप्त करना चाहूंगा कि एक पोलिटिकल मूवमेंट चलाने की जरूरत है। उपसभाध्यक्ष जी, कोई पालिटिकल पार्टी कश्मीर वेली में काम नहीं कर पाती है। हमारी पार्टी के तमाम लोग भाग करके चले आए, हमारे राज्य सेक्रेटरी की हत्या हो गई। इसके बाद से सब कोई जम्मू में पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का कुछ असर है। उन...

लोग भी भागे हुए हैं। नेशनल कानफ्रेंस के लोग भी भागे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि यह कम्युनिस्ट पार्टियां, नेशनल कानफ्रेंस के लोग, कांग्रेस के लोग या इस तरह जो लोग हैं-- मैं शर्मा जी की पार्टी का नाम लेता,.....लेकिन वह तो वहां जा करके यह हल्ला शुरू करने लगेंगे तब तो दूसरे ही झंझट में पड़ जायेंगे। इसलिए इनको हटा दें। अन्य पार्टी के लोगों का हम चाहेंगे कि एक मूवमेंट चलाया जाए और इसके लिए एक रेसपांसिबल बाडी कायम हो। जनता से संपर्क कायम किया जाए और उनको बताया जाए। यह संपर्क अब आप का मजबूत होगा तभी कुछ किया जा सकता है। वहां तो मिलिटेंट लोगों ने इस ब्रिज को तोड़ दिया है। गांव के भीतर आर्मी जा नहीं सकती और जाएगी तो क्या करेगी? गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई है। खुफिया व्यवस्था फेल हो गई है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mishraji, please conclude.

SHRI CHATURANAN MISHRA; I am concluding. I am making the last point.

ऐसी हालत में एक पोलिटीकल मूवमेंट इसके लिए चलाया जाए। हमारे प्रधान मंत्री तो काफी बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और ज्ञानवान भी हैं। लेकिन सब ज्ञान रहने ही से तो काम नहीं हो जाता है। नयी पेशकदमी भी हो उनको जिसका हमको लग रहा है कि उनमें अभाव है। तो यह पेशकदमी करके ऐसा आंदोलन चलाएं तो कुछ वर्षों के बाद काश्मीर की समस्या के निदान को हम देख सकते हैं वरना अभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में मैं उन बातों का विरोध करता हूं जो कुछ अमरीका के लोग हमारे खिलाफ प्रचार करते हैं। यह हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो लगातार भारत के खिलाफ कर रही है भारत के खिलाफ प्रोपेगंडा का कहीं से भी मैटीरियल मिल जाए और हमारी सरकार इसका सही जवाब नहीं दे पा रही है और वही लोग टैरोरिस्टों को ट्रेंड भी करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude. You are going beyond the time allotted to **you,** and the time-schedule is going out of order.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, is the Minister replying today or tomorrow?

श्री चतुरानन मिश्र: दस हजार आदमी ट्रेंड करके पाकिस्तान ने आर्मी के बकौल खड़े किए हैं जिसमें आप दो सौ, तीन सौ को पकड़े हैं तो बाकी का क्या होगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर होम मिनिस्ट्री रहती तो इसका जवाब दे पाती। जहां तक ला मिनिस्ट्री का है यह तो एक छोटा सा सवाल टेक्नीकल सवाल है, हम उनका साथ देते, लेकिन बड़ा पेनफुल है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA) The Business Advisory Committee is sitting now. We shall have to wait for its recommendations. Only then will we be able to tell you. After the adjournment of the meeting of the Business Advisory Committee we shall be able to tell you up to what time we shall sit. We shall have to wait for the recommendations of the Business Advisory Committee. So, up to that time we shall have to sit here.

SHRI A. G. KULKARNI: I am requesting that the reply should be given tomorrow.

SHRI S. S. AHLUWALIA: The allotment of time for the business can be read out tomorrow.

SHRI A. G. KULKARNI: Whatever the Committee may decide, when the reply should be given is our discretion. The House desires that the reply should be given tomorrow. We can sit if they want or if somebody wants to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Khaleeludr Rahman. The time allotted for you is eight minute

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश): जनाब वाइस चेयरमैन साहब, रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्ज (अमेंडमेंट) बिल, 1991 जो पेश किया गया है हकूमत की जानिब से मैं मख्सूस हालात में इस बिल की ताईद करता हूं। जनाब वाइस चेयरमैन साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी हाल जो हमारे जनरल इलैक्शज हुए, भारत की लोक सभा के लिए, वह पूरे मुल्क में हुए, सिवाय जम्मू और काश्मीर के। होना तो यह चाहिए था कि यह इलेक्शन पूरे मुल्क में होते, मगर जो मख्सूस हालात रियासते जम्मू और काश्मीर में हैं, उन हालात को पेशे-नजर रखते हुए वहां पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। अभी हमारे अहलुवालिया जी और भंडारे जी ने यह कहा कि यह जो हालात जम्मू और काश्मीर में पैदा हुए, वह जो है वहां की असेंबली को डिजाल्व करके प्रेसीडेंट रूल लगाने के बाद, वह हालात पैदा हुए हैं। मगर मैं उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता, कई सालों से वहां पर जम्मू और काश्मीर में इस किस्म के हालात पैदा हुए। जब कांग्रेस की हकूमत थी यहां पर मरकज में और वहां फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी हमने देखा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरम्यान जो क्रिकेट मैच खेला गया था उसमें भी इस किस्म के हंगामे हुए थे और खास तौर पर कहा यह जाता है कि जितने भी इलेक्शज जम्मू और काश्मीर में लड़े गए, ख्वाह वह लोक सभा के हों या असेंबली के हों, उन इलेक्शज में रिगिंग की गई। और फिर वहां की हुकूमत में भी एक किस्म के निपोटिज्म के तौर पर वे लोग काम करते रहे, ओहदे जो देते गए, वे सिर्फ रिश्तेदारों को देते गए, अजीज अखारिब और दोस्त साहबान की बिरादरी को ध्यान में रखते हुए वहां काम किया गया। तो जाहिर है कि इस किस्म के हालात से वहां के आवाम में एक किस्म की बेचैनी पैदा हुई और उस बेचैनी का असर हम देख रहे हैं कि टेरेरिज्म की शक्ल में हुआ है। अभी हमने देखा कि वहां कई वाकयात किडनेपिंग के हुए। खुद हमारे साबिक वजीरे दाखिला मुफ्ती सईद की साहिबजादी रुबैया का और फिर हमारी पार्लियामेंट के नेशनल कांफरेंस के मेंबर सोज साहब की साहिबजादी का किडनेपिंग, एल०आई सी के अफसर का कत्ल और वहां के मशहूर लीडर मोलवी फारुख का कत्ल हुआ और अभी आपने देखा कि दुरैस्वामी को किडनेप किया गया है। ये सब वाकयात ऐसे हैं कि अभी भी वहां के हालात अच्छी तरह से काबू में नहीं आ सके हैं। लिहाजा वहां पर इस बात के कतई इंतजामात नहीं हैं कि फेअर एंड फ्री इलेक्शस हो सकें। इन बातों को सामने रखते हुए यह बात महसूस की गयी कि जम्मू-काश्मीर के इलेक्शस को फिलवक्त रोक दिया जाए और वहां पर उसी वक्त इलेक्शस कराए जाए जबकि हालात साजगार हों और फ्री एंड फेअर इलेक्शस हो सकें।

जनाब वाइस चेयरमैन साहब, अभी आर्टिकल-370 की बात की गयी। हमारे बी जे०पी के साथियों की जानिब से आर्टिकल 370 को निकालने की जो बात हो रही है, उससे भी जम्मू-काश्मीर की आवाम में एक किस्म का डर और खौफ है। वह इस वजह से कि तमाम कमानियत के साथ आर्टिकल-370 दिया गया था, तो फिर क्या वजह है कि आर्टिकल 370 को बर्खास्त किया जा रहा है। लिहाजा इस बात की जरूरत है कि वहां की आवाम के जैहन में, उनके खलूब में यह बात पैदा की जाय कि आर्टिकल-370 को कतई नहीं हटाया जाएगा और आर्टिकल-370 कायम और बरकरार रहेगा। जब जम्मू काश्मीर के आवाम में यह बात पैदा हो जाएगी कि आर्टिकल 370 के हटने की बात किसी सियासी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है तो आप यकीन मानिए कि वहां के हालात खुद-ब-खुद बेहतर हो जाएंगे। लिहाजा मैं हमारे साथियों से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप बराए-करम आर्टिकल -370 को हटाने की बात न कीजिए ताकि वहां के आवाम में एक तरह का सुकून और इत्मीनान पैदा हो सके।

अब जरूरत इस बात की है कि वहां के हालात को दुरुस्त करने के लिए चंद इंतजामात किए जाए। क्योंकि टाइम

कम है और बातें बहुत कहनी हैं, मैं सिर्फ चंद तजावीज आपके तवस्सुर से हुकूमत को पेश करना चाहता हूं। वहां पर खास तौर पर फलों की जो पैदावार है और खास तौर से सेब की जो पैदावार है, उसमें सेब उगाने के लिए लोगों की हिम्मत-अफजाई की बेहद जरूरत है। उनको सेब उगाने के लिए हुकूमते हिंद की जानिब से मदद दी जानी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते दूरदर्शन पर जम्मू-काश्मीर के ताल्लुक से एक न्यूज रील बताई गई थी। उसमें यह भी बताया गया कि इस साल वहां फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। अब इस बात की भी जरूरत है कि वहां जो भी फसलें होती हैं, वहां की जिरात को भी बढ़ावा दिया जाए। साथ ही पिछले दो साल से हम यह देख रहे हैं कि वहां का टूरिज्म मुतासिर हो गया है। जम्मू काश्मीर की आमदनी का इनहसार तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से होता है। लिहाजा इस बात की जरूरत है कि टूरिज्म की जो सनअत है, उसको तरक्की दी जाए। खास तौर पर बाहर से आने वाले जो फरिन टूरिस्ट्स हैं, उनमें यह खतरे का एहसास खत्म किया जाना चाहिए कि रियासते जम्मू और काश्मीर में अगर वे आएं, तो उनके लिए वहां कोई खतरा है। यह खतरा, यह बात, यह अंदेशा उनके जेहनों से निकाल देना चाहिए और जो वहां की टूरिज्म की सनअत है उसको भी तरक्की दी जाय।

जब यह हालात मामूल पर आ जाएंगे तो यकीनन एक अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में वहां इलेक्शन होगा और वह इलेक्शन ऐसा होगा, बिल्कुल फेयर एण्ड फ्री इलेक्शन होगा। उसमें जो भी नुमाइंदे आएंगे, वह सही मायनों में आवाम के हकीकी नुमाइंदे होंगे।

इन चंद बातों के साथ जो आपने मुझे टाइम दिया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं।

†[شری محمد خلیل الرحمان (آندھرا پردیش) : جناب وائس چیر مین صاحب - ریپریزینٹیشن آف پیپلز امینڈمینٹ بل ۱۹۹۱ جو پیش کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے میں مخصوص حالات میں اس بل کی تائید کرتا ہوں - جناب وائس چیر مین صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ابھی حال میں جو ہمارے جنرل الیکشن ہوئے - بھارت کی لوک سبھا کیلئے یہ پورے ملک میں ہوئے سوائے جموں اور کشمیر کے - ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ الیکشن پورے ملک میں ہوتے - مگر جو مخصوص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے - وہاں پر الیکشن نہیں کروائے گئے - ابھی ہمارے آہلووالیہ جی اور بھنڈارے جی نے کہا کہ جو حالات - جموں اور کشمیر میں پیدا ہوئے وہ جو ہیں وہاں کی اسمبلی کو ڈزالوو کرکے پریسیڈنٹ رول لگانے کے بعد وہ حالات پیدا ہوئے - مگر میں انکی بات سے اتفاق نہیں کرتا - کئی سالوں سے وہاں پر جموں اور کشمیر میں اس قسم کے حالات پیدا ہوئے - جب کانگریس کی حکومت تھی یہاں پر مرکز میں اور وہاں پر فاروق عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

جو کرکٹ میچ کھیلا گیا تھا - اسمیں بھی اس قسم کے ہنگامے ہوئے تھے اور خاص طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی الیکشنز جموں اور کشمیر میں لڑے گئے - خواہ وہ لوک سبھا کے ہوں یا اسمبلی کے ہوں - ان الیکشنز میں رگنگ کی گئی - اور پھر وہاں کی حکومت میں بھی ایک قسم کے نیپوٹزم کے طور پر وہ لوگ کام کرتے رہے - عہدے جو دیئے گئے وہ صرف رشتہ داروں کو دیئے گئے - عزیز و اقارب اور دوست صاحبان کی برادری کو دھیان میں رکھتے ہوئے - وہاں کام کیا گیا - تو ظاہر ہے اس قسم کے حالات سے وہاں کے عوام میں ایک قسم کی بےچینی پیدا ہوئی اور اس بےچینی کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررورزم کی شکل میں ہوا - ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں کئی واقعات کڈنیپنگ کے ہوئے- خود ہمارے سابق وزیر داخلہ مفتی سعید کی صاحبزادی روبیہ کا اور پھر ہماری پارلیمنٹ کے نیشنل کانفرنس کے ممبر سوز صاحب کی صاحبزادی کا کڈنیپنگ- ایل آئی سی کے افسر کا قتل اور وہاں کے مشہور لیڈر مولوی فاروق کا قتل ہوا اور ابھی آپنے دیکھا کہ دورے سوامی کو کڈنیپ کیا گیا ہے - یہ سب واقعات ایسے ہیں کہ ابھی بھی وہاں کے حالات اچھی طرح سے قابو میں نہیں آسکے ہیں - لہذا وہاں پر اس بات کے قطعی انتظامات نہیں ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو سکیں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات محسوس کی گئی کہ جموں کشمیر کے الیکشنز کو فی الوقت روک دیا جائے اور وہاں پر اسی وقت الیکشنز کرائے جائیں - جبکہ حالات سازگار ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکیں -

جناب وائس چیئرمین صاحب- ابھی آرٹیکل ۳۷۰ کی بات کی گئی- ہمارے بی جے پی کے ساتھیوں کی جانب سے آرٹیکل ۳۷۰ کو نکالنے کی جو بات ہو رہی ہے اس سے بھی جموں کشمیر کی عوام میں ایک قسم کا ڈر اور ہے - وہ اس وجہہ سے کہ تمام کمانیمٹ کے ساتھ آرٹیکل ۳۷۰ دیا گیا تھا - تو پھر کیا وجہہ ہے کہ آرٹیکل ۳۷۰ کو برخاست کیا جا رہا ہے - لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں کے عوام کے ذہن میں - انکے قلوب میں یہ بات پیدا کی جائے - کہ آرٹیکل ۳۷۰ کو قطعی نہیں ہٹایا جائیگا - اور آرٹیکل ۳۷۰ قائم اور برقرار رہے گا - جب جموں کشمیر کے عوام میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ آرٹیکل ۳۷۰ ہٹنے کی بات کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے - تو آپ یقین مانئیے کہ وہاں کے

حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے- لہذا میں ہمارے ساتھیوں سے درخواست کرونگا کہ آپ برائے کرم آرٹیکل ۳۷۰ کو ہٹانے کی بات نہ کیجئے تاکہ وہاں کے عوام میں ایک طرح کا سکون اور اطمنان پیدا ہو سکے -

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے حالات درست کرنے کیلئے چند انتظامات کئے جائیں - کیونکہ ٹائم کم ہے اور باتیں بہت کہنی ہیں - میں صرف چند تجاویز آپ کے توسط سے حکومت کو پیش کرنا چاہتا ہوں - وہاں پر خاص طور سے پھلوں کی جو پیداوار ہے اور خاص طور سے سیب کی جو پیداوار ہے اسمیں سیب اگانے کیلئے لوگوں کی ہمت افزائی کی بیحد ضرورت ہے - انکو سیب اگانے کیلئے حکومت ہند کی جانب سے مدد کی جانی چاہئے - ابھی پچھلے ہفتے دوردرشن پر جموں کشمیر کے تعلق سے ایک نیوز ریل بتائی گئی تھی - اسمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس سال وہاں فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں- اب اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں جو بھی فصلیں ہوتی ہیں - وہاں کی زراعت کو بھی بڑھاوا دیا جائے - ساتھ ہی پچھلے دو سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا ٹورزم متاثر ہو گیا ہے- جموں کشمیر کی نی آمد کا انحصار تو صرف ٹورزم سے ہوتا ہے لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹورزم کی جو صنعت ہے اسکو ترقی دی جائے - خاص طور پر باہر سے آنے والے جو فارن ٹورسٹس ہیں - انہیں یہ خطرہ کا احساس ختم کیا جانا چاہئے کہ ریاست جموں اور کشمیر میں اگر وہ آئے تو انکے لئے وہاں کوئی خطرہ ہے - یہ خطرہ یہ بات یہ اندیشہ انکے ذہنوں سے نکال دینا چاہئے - اور جو وہاں کی ٹورزم کی صنعت ہے اسکو بھی ترقی دی جائے -

جب یہ حالات معمول پر آ جائیں گے تو یقیناً ایک اچھے ماحول میں خوشگوار ماحول میں وہاں الیکشن ہوگا اور وہ الیکشن ایسا ہوگا - بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا - اسمیں جو بھی نمائندے آئیں گے وہ صحیح معنوں میں عوام کے حقیقی نمائندے ہونگے-

ان چند باتوں کے ساتھ جو آپنے مجھے ٹائم دیا اسکا میں شکریہ ادا کرتا ہوں -]

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now, Mr. Shabbir **Ahmad** Salaria. You shall have to conclude with in five minutes.

श्री शब्बीर अहमद सलारिया (जम्मू और कश्मीर) : सदरे आला, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया । यहां पर यह कहा गया कि आर्टिकल 370 ही कश्मीर के मौजूदा हालात की वजह है और यह आर्टिकल टेम्परेरी प्रोवीजन है । यह कृष्ण लाल जी

[श्री शब्बीर अहमद सलारिया

ने फरमाया । दरअसल कृष्ण लाल जी मुख्तलिफ औकात पर यह बात कहते हैं और मैं समझता हूं कि यह वक्त है कि उनको गलतफहमी को दूर कर दिया जाए।

आर्टिकल 370 हमने हिंदुस्तान के आईन में नहीं रखा । आर्टिकल 370 रखने की वजह यह है कि महाराजा हरि सिंह ने तीन या चार सब्जेक्ट पर भारत के साथ इलहाक किया, जब पाकिस्तान ने इस पर हमला किया । उससे पहले इलहाक करने के लिए तैयार नहीं थे । पाकिस्तान का डंडा उसको चढ़ा और वह मजबूर हुए । उन्होंने यहां पर इलहाक किया । जो इलहाक-नामा यहां पर कबूल किया गया लार्ड लुईस माउण्टबेटन और मिस्टर जवाहर लाल नेहरू के साथ और युनाइटेड नेशन में आपने कहा कि यह इलहाक जो है, हमको तब तसलीम होगा, जब जम्मू और कश्मीर की आवाम एक प्लेबिसिट के जरिए अपना फैसला करे । लिहाजा आईने हिंदुस्तान में आपने खुद टेम्परेरी दर्जा कर दिया । हमारा क्या कसूर है ? आईने-हिंदुस्तान में,

In the Constitution of India it was described as something temporary. Why? The Maharaja of Kashmir acceded to you on limited accession, on four subjects. You yourself said "This accession is not acceptable except as and when the people of Kashmir by a resolution or by a plebiscite agree to it.

लिहाजा आपने उस वक्त आईन में यह बात रखी । युनाइटेड नेशन में जाकर आपने कहा । अब आप यहां पर कह रहे हैं, यह टेम्परेरी हमने इसलिए रखा था कि इसको किसी दिन तोड़ दिया जाए । ऐसी बात नहीं है । कम से कम अपने इतिहास को पढ़ा कीजिए, कम से कम अपनी हिस्ट्री को देखिए, कम से कम उन वाकयात को देखिए जिनकी बुनियाद पर इस आर्टिकल 370 को रखा गया । ठीक है यह आर्टिकल 370 टेम्परेरी है । क्यों टेम्परेरी है?

It is temporary because your yourself said that it will be temporary. It Is temporary because you said that the of Kashmir will be decided by the people of Kashmir by a plebiscite. It is you who said it. It is the Government of India which gave birth to the idea of a plebiscite in Jammu and Kashmir. lt is not anybody else. So it is your creation. It is not their creation.

"I shall not be bound by any Constitution

दूसरा आप फरमाते हैं कि 1976 में आईने-हिंद में तरमीम की गई और तरमीम करने के बाद उसमें अलफाज सेकुलर और सोशलिस्ट लिखे गए, लेकिन यह अलफाज कश्मीर के लिए हावी नहीं होंगे । अनफोर्चुनेटली, बी जे पी को यह पता नहीं है कि कश्मीर का अपना आईन है क्योंकि जब हरि सिंह ने भारत के साथ इलहाक किया था तो उसने वाजेह तौर पर कहा था—

of India".

लिहाजा आपने उनको हक दिया कि वह अपना आईन बनाएं और उन्होंने अपना आईन बनाया और अपने आईन में यह अलफाज सोशलिस्ट और सेकुलर आज से कई साल पहले उन्होंने लिख दिए, कश्मीर के लोगों से हमारा आईन जो है, उससे बहुत ज्यादा पसमांदा आईन है ।

Our Constitution was so backward as compared to the Constitution of Jammu and Kashmir.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : आप कोट करो जम्मू-कश्मीर के आर्डर को ।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : मै कह रहा हूं । मैं एक लॉयर हूं मेरा काम ही कानून पढ़ना है । आप उनका आईन पढ़ें जम्मू-कश्मीर के आईन में । पहले ही लिखा था—सेकुलर और सोशलिस्ट । आपको बाद में याद आया । लिहाजा इसको दुबारा वहां क्या करना था ? फिर यह फरमाते है कि रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का 29 (ए) वहां हावी नहीं है । किस बात की दुहाई देते हो ? आपकी कन्करेंस लिस्ट तो वहां हावी नहीं

है, वहां पर तो आपकी जो सेंट्रल लिस्ट है, जो लिस्ट नम्बर एक है, वह हावी है और उस लिस्ट को रूह में रिप्रजेंटेशन आफ दि पीपुल्स इलेक्शन लॉ जम्मू-कश्मीर में वह स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट ही नहीं है, लिहाजा How can section 29(a) incorporated by Parliament be enacted in Jammu and Kashmir? And it is a sorry state of affairs that Members of Parliament, without studying law, make speeches and make certain assertions here which have no basis in the eve of law.

फिर कहा गया कि जम्मू और कश्मीर नॉन सैक्यूलर है। जम्मू डिवीजन में 6 जिले हैं और उन 6 में से 3 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां पर कोई टरमाएल नहीं है। यह इसके नॉन सैक्यूलर होने का सबूत है या सैक्यूलर होने का सबूत है। लद्दाख में मुस्लिम मेजारिटी है, वहां पर किसी किस्म का आतंकवाद नहीं है। लेकिन वादी-ए-कश्मीर के अंदर यह हालात पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

The present question is; How are we going to improve the situation in Kashmir. The situations should be improved with a view to hold elections in Kashmir. Firstly, in the present operations done in Kashmir, obviously thousands of people have been held on the basis of suspicion. Will it not be proper to constitute a body consisting of a member of BJP, a member of the Congress and a member of the National Conference and a nominee of the Government? They should sit together and review those cases, the cases of people whom you have taken into custody simply because they are suspect and who have committed no over act. Then send a good message to the people of Kashmir that you are releasing the innocent people. Why don't you do that?

Secondly, in Kashmir, you have got a Government which has proved to he counter-productive. You have a Government of bureaucrats, people totally divorced from the life in Kashmir. And there is total corruption and there is no liaison between the people and these bureaucrats. Why dont you think of these things? I tell you honestly that it is in the interests of the country, in **the** interests of the nation, to change that ad ministration. Have people who have a political background. Have people who have a social background. Have people who will be capable of developing liaison with the people. Let a man from the BJP, a man from the National Conference and a man from the Congress be the advisers of the Government. **But** please change the system if you have to save Kashmir.

Mr. Bhandare gave very good suggestions. He has said that there is large-scale unemployment in Kashmir. The BJP and the hon. Minister may kindly also consider this. These unemployed are the breeding ground for the other side. They are their ground for recruiting people. If those who have gone to the other side come down, lay down arms and agree to live in the national mainstream, what grievance have yon with that? If those who are engaged in these activities today lay down arms, come to you and say, "All right. We accept whatever is there and we are sorry for what we did", why don't yon accept it. We have to set things right. As Mr. Bhandare said, why don't you employ the educated youth whom they are employing? You employ them. Today if you start talking of service rules, advertisements, competitive examinations, it will not help. You cannot solve **and** extraordinary condition by ordinary means.

T think these things need consideration in order that my friends may appreciate them, in order that the Government which is lying oblivious to what should be done in Kashmir may know it. They have no policy at all in Kashmir. They have not taken any concrete steps in Kashmir. They just send Governments and some bureaucrats and thing that **the** Kashmir situation will be solved. **The** other side is doing many things and yon are doing nothing. In the circuinstances, therefore, I commend Mr. Murlis suggestion that the young people who are eligible and who could he recruited is

[श्री शब्बीर अहमद सलारिया

various services should be recruited. Another suggestion made by Mr. Bhandare is very valid in which he said, Don't think that in Kashmir, IAS and IPS officers sent from other parts of the country can be more successful". You take people from Kashmir. You involve the people of Kashmir in the running of the administration and you will find the results will be far better. Those people who come from outside, they take many years to understand the problems and they do not know the ground reality. They do not know the language. Therefore, it is necessary that this attitude should be changed and the local administration should be associated with it.

It has been said that there are certain allegations against the army. True. There are allegations. But those allegations are not against the army. The army remained for 1 month in Anantnag. The people of Anantnag actually mourned the day the army was withdrawn. I tell you, please have the army and the local police in side Kashmir. Send the BSF and the CRPF to the border and you will find a seachange in Kashmir. People don't have complaints against the army. They have complaints against the paramilitary forces and those complaints are there in other parts of India also. Why do you talk of Kashmir alone? There are so many riots in India in which there are complaints against the paramilitary forces. But whenever army is deployed even in other parts of our country, there is no complaint. There is no complaint in Kashmir also. There are complaints of rape, there are complaints of excesses and these are elienat-ing the people. These can be done away with provided you discipline your forces. Secondly let the local police be involved. The local police has been sidelined. They only know the true position. The local administration has been sidelined. They alone know the true position. For God's sake, the Home Ministry should rise from deep slumber and realise what I am telling you. Tomorrow, it will be too late. Involve the local administration, involve the local police and ask the army to be with them. You will find the result will be better. I will request you to take positive steps in order to set the conditions in Kashmir right Speeches will not set them right. Please take into consideration the suggestions which I have given and discuss them with us and you will find that the problem will be solved within six month's time. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); Prof. Sourendra Bhattacharjee. You have been allotted six minutes.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: One or two minutes from your quota, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Earlier, you were allotted four minutes. I have added two more minutes.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Sir, Mr. Bhandare dilated on the strength of our democracy. Naturally, with Mr. Bhandare, myself and all other Members of the House—Mr. Ahluwalia is included— together with our boycott of his speech, which is also the strength of democracy, the strength of democracy should not be in doubt. That is the first point. The second point, perhaps, may not be that transparent to many but to many more, it is very transparent regarding the machinery to carry on the democratic process in the country, that is the august body of Election Commission and august office of the Chief Election Commission, The atmosphere of Election Commission before Mr. Seshan and after Mr. Seshan show—the term which has been repeatedly used—a sea-change. From being a citadel of democracy, it has became something of an antipathy to it. Even Members of Parliament are subjected to metal detectors and physical frisking. Even though it was pointed out in a delegation of M.Ps by Mr. Sukomal Sen that even in Rashtrapati Bha van, M.Ps are not required to go through metal detectors, that made no impression on the Election Commission which has been converted into a fortress and thh is an ominous sign for the democracy of our country.

even though its strength has been demonstrated again and again. Let it **not** be destroyed, subverted, browbeaten. The question of law has come up. This ordinance had to be promulgated because the original provision in the Representation of the People Act does not provide for exclusion of any part of Indian territory from the purview of **the** election. If I understood the Minister correctly, in order to fill up this gap on the recommendatiog of the .Election Commission this ordinance was introduced. So far as that aspect is concerned this exculsion might have been necessary but at the same tune it is necessary for the Government to answer the Government of the day naturally. And this development in Jammu and Kashmir which necessitated the exculsion of Jammu and Kashmir from the purview of the democratic process is a result of many factors, a cumulative effect over a long period. Now the question is we are putting a seal of approval, from the temporary ordinance to the permanent incorporation of an act but with what assurance regarding the restoration of democratic process in that part of the country which is entitled to democracy, democratic process, no less than other parts of the country? And the Administration of the country cannot escape the responsibility for the situation in which Jammu and Kashmir had to be excluded. But before that, you look at Punjab, the way its election process was stopped and Assam which was originally excluded from the mainstream of election. At the same time while stating this aspect the matter Mr. Bhandare talked of excesses in the complaints of human rights organisation. The question is quoted from the Report of **the** Press Council that it should have been more thoroughly checked but so far as I understand the function of the democratic rights organisation, whenever a *prima facie* doubt is there regarding **the** violation of democratic rights, a true democratic rights organisation must raise this issue and it is the responsibility of the powers that be to establish that there has been no violation. So raising of doubts regarding the functioning of **the** Army or the paramilitary forces in Kashmir is not in itself *prima facie* objectionable. But it may only serve as **a** safeguard that aspect has to be kept in mind.

Another point regarding the entire election process of our country is **this** The President of India issued a notification regarding the election in all parts of the country, barring Punjab and Jammu and Kashmir and to constitute the **Lok** Sabha by the 5th Of June. After **this** the tragic event of our Rajiv Gandhi's assassination took place. Till then **only** the first phase of election was over. I don't remember earlier such phases **had** been there in respect of elections. Anyway, the first prise was over and on **20m** May and on 21st May at 10.45 **tha** tragedy occurred. This was a **very** tragic event no doubt and naturally **the** election process immediately following might not have been possible to be continued. But what is objectionable is that the Election Commission revised **the** entire election process without a further notification from the President. The Presidential notification till then emphasised that Lok Sabha would be constituted on 5th **of June.**

The election process continued up to 19th of June according to the Notification of the Election Commission. But the President did not revise the last **date** of constituting the Lok Sabha. It **was** done later. The Chief Election Commissioner met the President, but meeting the President getting his verbal approval to the change is not enough, **not** even legal and , therefore, this change was made unconstitutionally and **the** President by issuing post facto approval of what was done by the Election Commission did violate the constitutional provisions in this regard. I request **the** hon'ble Law Minister to examine this aspect as to whether in doing this **the** President remained silent over his responsibility and the Election Commission transgressed its limits. Thank you, Mr. Vice-Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (DR- NAGEN SAIKIA): I thought that we could save five minutes of time. But Shri Ram Awadhesh Singh has already come. Now, Ram Awadheshji, the time allotted to you is five minuets.

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने आया है, वह एक औपचारिक बिल है। इसको स्वीकृति देनी ही है चूंकि जो अध्यादेश राष्ट्रपति जी का था उसकी जगह पर कानूनी कवर देना है। इसलिए इसके विरोध में बोलने का सवाल नहीं है। इसलिए इस बिल का समर्थन करना लाजिमी है।

श्रीमन इस बिल की ओट में जो भाषण हुए हैं कांग्रेस की तरफ से और कुछ सदस्यों की तरफ से उनके बारे में मुझे कहना है। अहलूवालिया जी के बारे में मैं क्या कहूं।...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : हम एक साथ आए थे और एक साथ जाएंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : कोई राजनीतिक आदमी हो तो उसके बारे में कहूं। ये तो राजनीतिक रहे नहीं, लेकिन राजनीति का रस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि चुनाव कराने के जो इरादे थे सरकार के उसमें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग ढंग से सरकार ने निर्णय लिए। चुनाव की घोषणा के बाद पंजाब और असम में भी चुनाव कराने का ऐलान हुआ। यह भी कहा जाता था कि वहां भी चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव होने पर वहां की सत्ता बदल गई, असम की, और पंजाब में भी कोई नतीजे आते जरूर। जब जब यहां बहस होती रही है पिछले चार साल से मैं यही सुनता हूं कि जो बड़े बड़े नेता बोलते हैं, हर दल के बोलते हैं, कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब उनके दल के हित में वह राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होती है कि नहीं, इसके आधार पर वह फैसला करते हैं चाहे कश्मीर हो, चाहे असम हो, चाहे पंजाब हो। पंजाब में चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, कुछ ही घंटे बाकी रह गए थे। यह तय हो गया था कि कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में बने। कांग्रेस ने पीछे से यह चाहा कि चुनाव को टालने की बदनामी हम न लें इसलिए नरसिंह राव जी ने शपथ बाद में ली पहले चुनाव को टाल दिया गया। जो चुनाव टाला गया वह खुद अपनी सरकार के फैसले के अनुसार टाल सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ओट में आकर इस मौजूदा सरकार ने यह किया। क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव का बायकाट किया था इसलिए वह चाहती थी कि हमारी बात रह जाए। गुड़ खाये और गुलगुलों से परहेज। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं यह घोर अनैतिक कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया है कि चंद घंटे पहले पंजाब में चुनाव को रोका गया। मैं यह कई बार कह चुका हूं कि अगर चुनाव हो जाते तो आपका क्या जाता। मुझे भी लगता था कि एक पार्टी की सरकार नहीं आ सकती थी और जब तक आपके हाथ में संविधान की धारा 356 का बटन है तब तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब परिस्थिति आपके काबू के बाहर हो जाए तो संविधान की धारा 356 के बटन को आप दबा सकते हैं। सरकार को स्वेच्छा से कभी भी आप खत्म कर सकते हैं। मैं इस बात को आज भी मानता हूं कि कश्मीर में चुनाव कराये जा सकते हैं। एक बार वहां के लोगों को भी मौका दिया जाता, खतरा उठाया जाता, राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जाती। यह बात जरूर है कि खतरनाक माहौल है और इससे हम लोग सहमत हैं। पाक से लोग आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। इसी आधार पर मैं यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की तराई में जो घटना घट रही है यह भी एक गड़बड़ वाली बात है। तमिलनाडु में जो हो रहा है, असम में जो हो रहा है वह आप सब लोग जानते हैं। यह ऐसी स्थिति है कि वहां की जनता को आपको इन्वाल्व करना होगा और नहीं तो कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। मुझे को तो ऐसा लगता है कोई बड़ी साजिश हो रही है कि

धीरे-धीरे सारे देश में वोट का राज खत्म कर दिया जाए। पहले एक सूबे में फिर दूसरे सूबे से और उसके बाद तीसरे सूबे से इस तरह से सारे प्रदेश से यह खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब है कि वोट के राज में एकजुट का राज हो जायेगा। वोट का राज चलेगा तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग एकजुट हो जायेंगे और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए वोट के राज को खत्म करने की गहरी साजिश है। मैं इसको गम्भीरता से लेता हूं।

जैसा अहलुवालिया साहब ने कहा कि बिहार में चुनाव नहीं हुए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि बिहार में चुनाव हुए, सही हुए। मैं हार गया, मुख्य मंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण हार गया लेकिन ऐसा नहीं है कि बूथ कैप्चरिंग हुई हो, मार-पीट हुई हो। पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग, आदिवासी...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : ये सब आपके साथ हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : मेरे साथ थे और आगे भी होंगे।
लेकिन वे अभी मेरे साथ नहीं थे, यह सच्चाई है। हो सकता है कि जो फसल मैंने तैयार की थी वह फसल किसी दूसरे के हाथ लग गई, लेकिन वह फसल मेरी तैयार की हुई थी। अभी मेरे हाथ नहीं लगी लेकिन खेत तो अपना है। अगली फसल आ जाएगी। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें बिलकुल सच्चाई की बात यह है कि श्री लालू यादव जो वहां के मुख्य मंत्री हैं उनका असर उनकी जाति यादव पर और अल्पसंख्यकों पर बहुत गहरा था। वे दोनों मिल गये और बाकी अन्य पिछड़ी जातियां भी उनके साथ मिल गये थे। बिहार में मुसलमानों और यादवों की संख्या 27-28 परसेंट अकेले हो जाती है। बिहार के बारे में कितने लोग बोले हैं... (व्यवधान)। बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि श्री लालू यादव का व्यक्तिगत प्रभाव इन दोनों कम्युनिटियों पर हुआ जिससे 27-28 परसेंट वोट एक साथ हो गये। लोहार, सुनार, तेली और कुम्हार आदि सभी उनके साथ एकजुट हो गये और वे जीत गये। मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी खूबी श्री लालू यादव की यह है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि जब से उन्होंने गद्दी संभाली है तब से एक भी रायट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में रायट्स बहुत हुए हैं, लेकिन बिहार में रायट्स नहीं हुए हैं। यह उनकी खूबी देन है। इस कारण से मुसलमान उनके साथ हो गये। इसलिए श्री अहलुवालिया जी का जो चार्ज है कि बूथ केपचरिंग हुआ, वह सही नहीं है ...(व्यवधान)। बैलट केपचरिंग तुम्हारे यहां हुआ होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सरकार का दिल मुर्गी जैसा है और प्राण कछुए जैसे हैं। कांग्रेस का दिल मुर्गी जैसा है और प्राण कछुए जैसे हैं। कछुए को लोग काटते हैं तो वह धीरे-धीरे मरता है। इसलिए कछुए जैसे प्राण वाले और मुर्गी जैसे दिल वाले अगर हुकूमत करने लगेंगे तो इस देश में जम्हूरियत की रक्षा नहीं की जा सकती है और न ही जनतांत्रिक प्रक्रिया ही कायम की जा सकती है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): At least be has concluded. We must thank him. Now, Mr. Ambedkar, the time allotted to you is five minutes.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I will limit myself to the legal aspect of it. Before I begin, I will read the objects of the Representation of the People Act from where the Chief Election Commissioner derives his power to recommend to the President:—

... An Act to provide for the com-duct of election to the Houses of Parliament and to the House or Houses of Legislature of each State the qualification and disqualification of the membership of those Houses the corrupt practices and other **offences at**

(Shri Prakash Yashwant Ambedkar) or in connection with elections and the decision on doubts and disputes arising out of or in. connection with such elections".

As far as the ambit Of the Act goes, if I may codify it, the first is regarding the powers of the Election Commissioner as to the conduct of eletcion, the second is the qualification of membership the third is disqualification of membership, the fourth is relating to the corrupt practices and offences in connection with the elections and the fifth is regarding decisions on' disputes or doubts arising out of or in connection with *the* elections.

So, before I examine section ■14(2) I will mention the powers of the Election Commission as derived by it under article 324 of the Constitution. Clause (1) of article 324 provides for the superintendence, direction and control, clause (2) deals with the manner of appointment of the Chief Election Commissioner, clause (3) deals with the Chairman of the Election Commission clause (4) deals with the staff, clause (5) deals with the Regional Com-misioners and clause (6) deals with the staff to be provided by the President or the Governor. If we see the ambit of the powers that are given to the Commission, we will find that there is no power which enables the Election Commission either to postpone the elections or to segregate the constituencies of Parliament or to give a date for the Parlia-mentary constituencies. This is what you find after examining section 14(2) and the recommendations which are to be given by the Election Commissioner and also if you read the qualifying words over there, that is, "For the same pur-.pose, the President by issuing one or more notifications to be published in the Gazette of India on sucn date or dates as may be recommended by the Election 'Commission,...". what is specifically empowering the Chief Election Commissioner oyer here is that he has to give either one date or more than one date on which the elections to all Parliamentary constituencies can be, held/ What is now sought to be- rectified in this House is this: The Chief Election Commissioner has already segregated . some seats of Parliament from the rest of the seats in the *country* and, in this case, the seats of Jammu and Kashmir have been segregated from the rest of India which is not allowed even by section 14(2) as it is constituted because elections are to be held in all the Parliamentary constituencies at one and the same time and if they cannot be held at one time, it is the duty of the Election Commissioner to state the dates on which he can hold the elections. The position is that while submitting to *the* President of India to issue the notification, all dates regarding Parliamentary constituencies have to be submitted to the President by the Chief Election Commissioner. What has been recommended and what has been stated here is, that the Chief Election Commissioner has recommended that elections for some seats should be postponed. The power of postponement, as I have stated already, both under the Representation, of the People Act. 1951. and under. article 324 of the Constitution of India, is not vested in him and these do hot empower the Election Commission either¯ to postpone it or even to give a date for some constituencies and- leave it for. the other Donstituencies. Therefore, according to me, the amendment that is sought to be made now does not fit into the ambit of the Constitutional powers as far as elections go.

And, therefore, I hope the Minister will think over it before asking this to be voted upon.

Thank you

THE VICE-CHAIRMAN (DR.. NAGEN SAIKIA): Minister to feply.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): I have got a right to reply.

THE VICE-CHAIRMAN {DR. NAGEN SAIKIA): Yes, it is a Resolution. I Shall only request you to be brief.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को एक संवैधानिक और इस विधेयक को कानून बनाने के लिए जो बहस चली, इस बहस के माध्यम से बहुत लोगों ने अपने मन के उद्गार सदन के सामने रखे कहीं कहीं ऐसा महसूस हुआ कि एक तरह से हमारा सब का लक्ष्य एक ही है कि देश में गणतान्त्रिक अधिकारों का हनन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये। परन्तु उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे रास्ते भिन्न हो सकते हैं, हमारी भाषा, परिभाषा और विश्लेषण अलग हो सकता है या विश्लेषण अलग हो सकता है परन्तु हमारा लक्ष्य एक ही है कि भारत के हर एक नागरिक को उसके पूर्व पुरुषो और इस देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों ने जो अधिकार दिये हैं वे अधिकार बरकरार रखना आज की मौजूदा सरकार के साथ साथ मौजूदा पार्लियामेंट के सदस्यों का लोगों के प्रतिनिधियों का फर्ज बनता है। उनका यह कर्तव्य है कि उनके अधिकारों का संरक्षण करें और संरक्षण करते हुए जिन जिन सदस्यों ने जो जो वक्तव्य रखे मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। भंडारे जी ने ह्यूमेन राइट्स की बात उठाई कुलकर्णी जी ने भी एक वैसी ही ह्युमेन राइट्स की बात कही। मालवीय जी ने कहा कि 6 महीने के अन्दर चुनाव होना चाहिये। यह सब की बात है सब का उद्गार है। उन्होंने एक अमेंडमेंट भी दिया है। सुकोमल सेन जी ने कहा कि हर हालत में डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिये, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिये। खलीलुर रहमान जी ने वैसी ही बात कही कि जम्हूरियत को किस तरह से बरकरार रखा जाए और मजबूत किया जाए। श्री शर्मा जी ने जरूर इतना कहा कि जम्मू और काश्मीर के बीच में जो एंड के जो है इसमें के को हटा कर जो में इलेक्शन करा देना चाहिये। ऐसा किसी का भी मत नहीं है और मैं इसको विरोध करता हूं। हिन्दुस्तान के तो दो टुकड़े हो गये पर एक स्टेट के दो टुकड़े नहीं होने चाहियें, किसी भी हालत में नहीं होने चाहियें। जम्मू-काश्मीर में जब इलेक्शन होंगे तो पूरे होंगे और 6 सीटों के होंगे, तीन तीन सीटों की बात नहीं करनी चाहिये। उन्होंने जो धारा 370 का मसला उठाया उसका जवाब मेरे से अच्छा हमारे आदरणीय चतुरानन मिश्र जी ने उसको दिया है और बड़े तथ्यों के साथ दिया है। मैं समझता हूं इन चीजों को सामने रखते हुए कम से कम आइंदा धारा 370 का सवाल हमें नहीं उठाना चाहिये। चतुरानन मिश्र जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसा जवाब बी.जे.पी. को दिया है और तरीके से दिया है। बी.जे.पी. ने भी मांग की पर आधी मांग की और आधे अधिकार छीनने की मांग की पर उसका जवाब बड़े अच्छी तरह से दिया है। सलारिया साहब ने कहा कि हम यदि अपने घर के लोगों का विश्वास नहीं करेंगे जब हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का विश्वास नहीं करेंगे तो बाहर वालों से कैसे काम ले सकते हैं। सलारिया साहब ने कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इनवाल्वमेंट होनी चाहिये, लोकल लोगों के साथ रेपोर्ट अच्छा होना चाहिये। हम चीज को मद्दे नजर रखते हुए हमें ख्याल करना चाहिये। राम अवधेश
6.00 P.M. सिंह जी ने पोलिटिकल होते हुए भी नान पोलिटिकल वक्तव्य रखा, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। प्रो. सौरीन्द्र भट्टाचार्य ने भी डेमोक्रेटिक नार्म्स के रेस्टोर करने की बात कही है। प्रकाश अम्बेडकर जी ने जो लीगल प्वाइंट उठाया वह लीगल प्वाइंट्स बहुत से लोगों के दिमाग में झलकता है, दिखाई पड़ता है। मेरे दिमाग में भी ऐसी बात थी कि यह एक लीगल लैकूना है। उसको समझने की जरूरत है। खैर, प्रकाश अम्बेडकर जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने कांस्टिट्यूशन बनाया था। उन्होंने भी यह बात उठायी। यह अच्छी बात है। उस पर मेहनत करने की जरूरत है। मेरी मंत्री जी को भी गुजारिश है जोकि ला और जस्टिस के मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं और खुद भी अच्छे शायर हैं कि वे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आइंदा ऐसा

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

बिल लाएंगे कि अगर उसमें कोई लैकुना है तो उसको दूर करके लाएंगे। मंत्री महोदय का यह पहला बिल है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पहले बिल में ये सदन को एश्योरेंस देंगे क्योंकि हम सबका लक्ष्य है कि वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम रेस्टोर होना चाहिए। हमें एश्योर करेंगे कि ये तुरन्त से तुरन्त वहां पर लोकल लोगों के साथ रैपो बना कर वहां चुनाव कराएंगे और पब्लिक की चुनी हुई सरकार बनाएंगे। ऐसा अगर एश्योरेंस देते हैं तो हम आगे विचार करेंगे।

SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM; Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to thank the hon. Member, Mr. Ahluwalia for having at last given me the opportunity to rise and place my views in reply.

Mr. Ahluwalia, right at the beginning, when he was moving his Statutory Resolution, very strongly deprecated the situation where in a State of the Union, we have not held eleciions, and he mentioned with a depth of feeling that it was a Right in our Constitution which the Forefathers enshrined to ensure that our country would be democratic. Not only himself, but many Members and many senior Members went on record to say that it is with a heavy heart that they support this, whether it was the hon. Member Mr. Murli Bhandare or Mr. Sukomal Sen or whether it was Mishra-ji or Ram Nareshji, everybody did voice his view quite strongly. Mr. Vice-Chairman, Sir, I too agree with them. It is not with a light heart, but with a heavy heart, we are bringing this, feeling very unhappy about the circumstances that this situation exists today in a State of our Union where we have not been able to hold elections either to Parliament or to Assembly. The fact is that whether or not the Chief Election Commissioner has the authority to fix the dates for election, I think, Section 14(2) of the Representation of the People Act, 1951, as amended is very categorical. Sir, with your permission, if I may read out the said provision—because my young friend comes from a family as mentioned by Ahluwaliaji, which really had much more to do with the framing of the Constitution than mine and many others—Section 14(2) reads that "for the said purpose, the President shall by one or more notifications"*—speaking of plurality— published in the Gazette of India on such date or dates as may be recommended by the Election Commission— date or dates as may be recommended by the Election Commissison—call upon all Parliamentary constituencies to elect Members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder." If one sees 14(1) it speaks of a General Election for the purpose of constituting a new House of the People. Therefore, it is quite clear that under 14(2) the Election Commission has the duty, the[e] bounden duty to recommend to the President date or dates. The Chief Election Commissioner found it fit to reocmmend to the President that immediately one cannot have elections in Jammu and Kashmir along with the rest of India... because he felt that circumstances are such that special security arrangements would have to be made. It cannot be gone into in a hurry. There was not sufficient manpower both administrative as well as security to have elections. So, he said, it would have to be on another date. He said that it has to be considered whether at all a notification can be umdelr Section **14(1)** without amending Section 73. It was not possible. And that is exactly the reason for which, in the earlier instances of both Punjab and Assam amendments had to be brought. Therefore, I do not want to go deep into the point. I could have this argued out with Ambedkarji later on. I think, most of us are quite upset that we have crossed the one hour limit already. But I can assure you, on the face of it. it may look that power does not exist but it does exist and has been exercised and has been upheld by the Supreme Court in various judgements.

But at the moment, there is an issue which is important, I think, to all of us and that is, how this Jammu and Kashmir reached this state of affairs and what was the final straw on the camel's back. People may say that this was one of those things that started from the days of independence. Our friends from the BJP very strongly have advocated article 370 to be removed. Obviously, they are trying to indicate that article 370 may have been the genesis of the problem. 1 beg to differ with them. According to me, article 370 in the Constitution is one of those articles which has kept Jammu and Kashmir with us and not allowed those divisive forces to dominate. But it was said that the real genesis of the total collapse of the political machinery or the political process in Jammu and Kashmir the last straw on the camel's back, was the dissolution of the Assembly in Jammu and Kashmir. Whether that was an act which was legal or illegal is something which I would not like to comment on, since the matter is pending in the High Court of Jammu and Kashmir and it is very much sub judice. But definitely (hat was an act which .was the final straw- on the camel's back where nothing was left in terms of even attempting to bring back political process. And that is why today I cannot stand here and say that on this day we shall have elections in Jammu and Kashmir. J cannot call upon the Chief Election Commissioner to sincerely start trying to find a date and fix a date and recommend to the President to have elections on this particular day in Jammu and Kashmir. The situation in Jammu and Kashmir, all of us know, is not normal

AN HON. MEMBER: What about Jagmohan?

SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM: I do not want to comment on personalities. I think, the personalities who have been of the past, let them be in the past. Let us not bring them into the present. It is past. But I would like to go into this point and I would like the hon. Members to consider this very seriously and that is, it is not enough that all of us give mere platitudes that we should restart the political process. There has to be real collectvie application of mind. My friend Mr. Ahluwalia would like an assurance from me and 1 am bound to give him that assurance not because of his Statutory Resolution but because the Constitution envisage so. We cannot dream of having any State where there is no political process going on. We have to make efforts to bring the political process back. We want elections. The democratic institutions must be safeguarded. Democracy must be protected. And whatever thing we have to do we have to do it as quickly as possible. The longer we delay-the more complicated the situation becomes and more difficult to resolve. Some suggestions have been given by many senior Members. One of the *very* important suggestions, I think, our Government would take into consideration very seriously is the question of real involvment of the people of Jammu and Kashmir in the services, in administration. That is the matter which even my leader, the late Shri Rajiv Gandhi, the former Prime Minister—who was assassinated in my own State, unfortunately—had categorically said on the floor of the House much earlier to the earlier dissolution of the Assembly which was referred to as the beginning of this problem. I would like to, at this stage, point out that after that, there was an elected Government in Jammu and Kashmir. There was a situation where an elected Government was brought even after that dissolution. General elections took place. The Government came—with or without coalition, that is different— and the Government did exist. Today, we have a situation where we are all floundering about trying to find out a manner in which we can bring back the political process. I would like to take this opportunity to plead with all the parties concerned that to bring back the political process in Jammu and Kashmir, we need collective thinking and collective action. Yes, with the BJP especially not pressing on Article 370. Mr. Vice Chairman, Sir. there were certain passing references to Punjab and whether Punjab election process was stopped underhand. This was also raised earlier many a time. But, I think it is high time it was net.

[Shri Rangarajan Kumaramangalam] The election process in Punjab was on. We came in after the election process was stopped. Somebody said that we did it by proxy. We have to be there to do it even by proxy. We have not even been there. It is under Article 15 (3) where the Chief Election Commissioner has the power to postpone the elections. He has not cancelled the election. To put it on record, let me clarify that the elections were not cancelled. He has only postponed the election for reasons to his satisfaction. He took the decision. I understand, totally on the basis of the information that was available at his disposal, the decision which is his responsibility which we think was correct because we always hold the view even when we were in the opposition, that the state of affairs in Punjab was not such that a free and fair election could have taken place. Merely, just (his one bit of statistics would satisfy the people. 23 candidates were killed out of 170. It is not a small number. If we had elections in Kashmir, God knows how many would have been killed. But, may I just point out that I am not happy? I beg to disagree. I am just pointing out that Punjab was not in a state of affairs where free and fair elections could have been held and I feel that the CEC took the right decision.

Regarding the elections in Bihar, sometody spoke of various elections having got together. May I just give one figure. 421 violent incidents took place in Bihar during this election. Repoll was ordered for 1021 booths. It is important that these figures are registered. Because they have been so large, I think the Guinness Book of Records might consider putting it within its scope for being recorded. The Bihar election is not something about which all of us would be proud. From the amount of violence that took place we all know that the election v/as not free and fair. It is not for us to comment. The courts will comment. Many cases are pending, election petitions are there. Elections for two Parliamentary Constituencies we know, were countermanded These -are matters which are not, for the moment, to be considered. But, I would, at this moment, take this opportunity to ask all the hon. Members

श्री चतुरानन मिश्र : बिहार में चुनाव में जो हिंसा हुई है वह बहुत निदनीय बात है मैं इसको पहले भी कह चुका हूं लेकिन इसके पहले जो चुनाव हुए उनसे कम आदमी इस चुनाव में मारे गए हैं और सब से ज्यादा आदमी मारे गए हैं आपके, डा. जगन्नाथ मिश्र के आदमियों द्वारा उन्हीं की कांस्टिटुएंसी में... (व्यवधान)

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM; Mr. Vice-Chairman, Sir, this is very unfair. Mr. Mishra is such a senior Member. If he gives proper notice. ..

.SHRI CHATURANAN MISHRA: Sixty Communist cadres were injured. You can go and see. *(Interruptions).*

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सदस्य के खिलाफ रिकार्ड में जा रहा है। इसे रिकार्ड से निकाला जाए। जगन्नाथ मिश्र इस हाउस के सदस्य रहे हैं। He is not a murderer or a criminal.

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने यह कहा कि जगन्नाथ मिश्र के आदमी के द्वारा किया गया है। वहां 60 कम्युनिस्ट कार्यकर्ता घायल पड़े हुए हैं, हास्पिटलाइज्ड हैं। आप चलिए, हम आपको दिखलाते हैं। I have not said that he is a murdrer. *(Interruptions)* I only said that it has been done by his men. *(Interruptions)*

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: Mishraji, will you permit me -to continue? Mr. Vice-Chairman, Sir, I think it is a little unfair because Mr. Jagannath Mishra is not here. At the same time, I would say that his statistics are misplaced. I can prove it to him if he puts a separate question I can prove it with records in private, or, here, on the floor of this

Mouse, that his statement is untrue and *cannot be* substantiated. I do not want to go into it now.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I challenge you. I have got the names , the names of the persons who were injured. The list is with me.

SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM: We shall go into it. 1 am always available, Mishraji. You have known me for many years.

I would like to thank the hon. Members, who have spoken, for the manner in which they have participated in the discussion. Normally, such a Bill is dealt with in a very casual manner. It is just automatic. Most of as support it because it, is inevitable, it is a *fait accompli* situation. But I am happy to note that the whole question of Jammu and Kashmir was brought in and discussed.

Sir, there are certain issues which have been brought to my notice with regard to an earlier question put by Dr. Bapu Kaldate. Qufistiori No. 462, dated the 28th February, 1991. This question was replied to on the basis of information that was made available to our Ministry at that time by the Election Commission. I will definitely ask the Electiou Com-. mission once again. But the affidavits filed before the Election Commission are in their custody, not ours. We shall look into it.

SHRl A. G. KULKARNI: My question was specific.

SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM: I shall look into the matter.

SHRI A. G. KULKARNI: The late Peri Shastri ordered an enquiry.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN **SAIKIA):** Mr. Kulkarni, the hon. Minister has said that he will look into the matter.

SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, when I request Mr. Ahluwalia to withdraw his Statutory Resolution, I do so while being in full agreement with his feelings. I assure him that the Government would take immediate steps, whatever is possible,—I hope he would also be fully participating in those steps that are taken to bring back the political process in Jammu and Kashmir so that we could have a democratically-elected Government there and a peaceful State which would go from step to step to progress. Thank you.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि सारे सदन की भावना हैं कि जम्मू एंड काश्मीर में जल्दी-से-जल्दी चुनाव कराकर वहां की जनता की सरकार बनायी जाय और बाहर के जो अफसर हैं, उनके हाथ में से नियंत्रण लेकर वहां के लोकल लोगों के हाथ में नियंत्रण दिया जाए, इन भावनाओं को मद्दे नजर रखकर मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया हैं कि वह जल्द-से-जल्द वहां पर गणतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करेंगे इन आश्वासनो पर मैं अपना स्टेटुटरी रिजोल्यशन वापिस लेता हूं ।

The Statutory Resolution was, by leave withdrawn,

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now I will put the motion.

The question is:

That the Bill further to amend the Representation of the People Act 1951, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. There is one amendment in clause 2. *Clause 2 (Substitution of new section for sections 73A and 73A A)*

SHRI SATYA PRAKASH MALAVI-YA: Sir, I move:

"That at page *2,* line 9, after the words "appropriate" the words "but not later than the expiry of sir months from the date of commencement of this Act" be inserted.

The question was proposed.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: In this clause it has been stated that the Election Commission may take steps to hold elections in such manner and on Such dates as it may deem appropriate. My submission is that no time-frame has been given. It gives unrestricted powers to the Election Commission to hold or not to hold elections. Everybody is agreed that the democratic process in Jammu and Kashmir should be ushered in us early as possible. Therefore, I move my amendment that instead of the word 'appropriate' the words "but not later than the expiry of six months from the date of commencement of this Act" be inserted. Let my amendment be acceped and if they are not able to hold elections within six months, they can again come before this House and get its approval.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); The question is;

'That at page 2, line 9, after the word 'appropriate' the words 'but not Inter than the expiry of six months from the date of commencement of' this Act be inserted."

The Motion was negatived

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKTA): The question is:

That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, *the Enaeting Formula and the Title were added to the Bill*

SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM: Sir, I move:

"That the Bill be passed.

7 *he question was put and the motion was adopted.*

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 16th July, 1991, recommended that the sitting of the House fixed for Monday, the 22nd July, 1941. be cancelled and the House may have a sitting on Saturday, the 20th July, 1991 and that there would be no Question Hour on that day.

The Committee also recommended that in view of the cancellation of the sitting of Monday, the 22nd July, 1991, the notices of Questions given for that day stand lapsed.

The Committee allotted time for Ooternment Business as follows:—

Business	Time allotted
1. General Discussion on the Railway Budget for 1991-92	3 days *i.e.* July 20, 24 and 25 1991.
2. General Discussion on the General Budget for 1991-92	3 days *i.e.* July 26, 29 and 30, 1991.

The Committee further recommended that the House should sit upto 6.00 P.M. daily and beyond 6.00 P.M. as and when necessary, for the transaction of Government Business.

The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-five minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 17th July, 1991.